सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते है और हलके से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते है।"

वर्ष 01, अंक 171, नई दिल्ली

रविवार, 03 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

3 दिन दिल्ली बंद: मेट्रो के लिए क्या है गाइडलाइन? कितने मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

संजय बाटला, संपादक

दिल्ली में इन दिनों जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाले बैठकों को ध्यान में रखते हुए तीन दिन तक दिल्ली बंद रहेगी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें वायरल हो रही हैं। जिसमें दावा किया जा रहा है कि जी20 बैठकों के दौरान मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाले बैठकों को ध्यान में रखते हुए तीन दिन तक दिल्ली बंद रहेगी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें वायरल हो रही हैं। जिसमें दावा किया जा रहा है कि जी20 बैठकों के दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।

अब इन अफवाहों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रायल ने एक वीडियो साझा कर लोगों के सभी सवालों का जवाब दिया है।

पूरी दिल्ली में उपलब्ध रहेंगी मेट्रो की सेवाएं: I&B मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में दो व्यक्ति एक-दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा शेयर वीडियो के अनुसार, नौ सितंबर, 2023 को शिखर सम्मेलन की बैठकों को दौरान पूरी दिल्ली में मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
हालांकि, मेट्रो के स्टेशन सुप्रीम कोर्ट पर नौ सितंबर, 2023 सुबह पांच बजे से 10 सितंबर, 2023 की रात 11 बजे तक एंट्री और एग्जिट की सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही मंत्रालय ने इस वीडियो और सही जानकारी को सबके साथ शेयर करने का अनुरोध किया है।
G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने की उम्मीद है।
दिल्ली में 18वां शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच आयोजित सभी जी20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Front Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-

- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

दिल्ली मैट्रो स्टेशनों सेअब चलेंगें ई-ऑटो, लेडीज भी चलाएगी ऑटो

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

राजधानी दिल्ली को सिस्टेमेटली तरीके से चलाने की कवायद के चलते मैट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डीएमआरसी फीडर बसों की जगह ईलैक्ट्रिक ऑटो चलाने जा रहा है। है।इसके लिए शुरूआत में एक निजी कंपनी 100 ईलैक्ट्रिक ऑटो चलाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एमप्लस पॉवर सप्लाई प्राईवेट लिमिटेड को ई-ऑटो के परिचालन के लिए बाकायदा लेटर ऑफ इंटेंट (एल ओआई) तक जारी कर दिया है। कंपनी को मैट्रो ने अधिकृत किया है। ईलैक्ट्रिक ऑटो विभिन्न मैट्रो स्टेशनों से चलेगे। इसका मकसद लोगों को उन कालोनियों तक कनेक्टिविटी देना है जहां कनेक्टिविटी मिलने में परेशानी है। इन ऑटो में 50 सामान्य ई-ऑटो होगें। जिन्हें कोई भी चला सकेगा। इसके अलावा 50 ईलैक्ट्रिक ऑटो जिन्हें सिर्फ महिलाए ही चला सकेगी। यह सुविधा दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुरोध पर दी गई है। इस बावत 3 मार्च 2022 और 7जुलाई को लेटर के जरिए परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डीएमआरसी को यह आवंटन नियमों और शर्तो के आधार पर अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में चलेंगी पीएम ई बसें, अगले पांच महीने में शुरू होगी सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद फरीदाबाद नोएडा कानपुर लखनऊपटना इंदौर और जयपुर उन 169 शहरों में शामिल हैं जिन्हें अगले पांच-छह महीने में शुरू की जा रही पीएम ई-बस सेवा के लिए चुना गया है। इस योजना को हाल में ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। बीस से चालीस लाख आबादी वाले शहरों में कोच्चि कोझिकोड नागपुर और कोयबंटूर भी हैं जहां इस बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

नई दिल्ली। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ,पटना, इंदौर, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और जयपुर उन 169 शहरों में शामिल हैं जिन्हें अगले पांच-छह महीने में शुरू की जा रही पीएम ई-बस सेवा के लिए चुना गया है।

शहरी परिवहन के लिए बड़ी और प्रभावशाली मानी जा रही इस योजना को हाल में ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। बीस से चालीस लाख आबादी वाले शहरों में कोच्चि, कोझिकोड, नागपुर और कोयबंटूर भी हैं, जहां इस बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

पीपीपी मॉडल में खरीदी जाएंगी दस हजार बसें

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने इस योजना को क्रांतिकारी कदम बताया है। केंद्र के बीस हजार करोड़ रुपये की मदद से पीपीपी मॉडल में दस हजार बसें खरीदी जाएंगी। ये वातानुकूलित बसें लोगों को मेट्रो में सफर जैसा अनुभव प्रदान करेंगी। मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें तीन श्रेणियों में वे शहर हैं जिन्हें इस योजना के लिए चुना गया है।

पहली श्रेणी से बीस से चालीस लाख आबादी वाले शहरों की है और दूसरी दस से बीस लाख तथा तीसरी, पांच से दस लाख। दूसरी श्रेणी के शहरों में चंडीगढ़, रायपुर, फरीदाबाद, श्रीनगर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, अमृतसर, लुधियाना, जोधपुर, कोटा, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गुरुग्राम, जम्मू, बोकारो स्टील सिटी, उज्जैन, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, जालंधर, अजमेर, बीकानेर, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, नोएडा शामिल हैं।

योजना में शामिल हैं 76 शहर

योजना में उन शहरों को खास तौर पर चुना गया है, जहां संस्थागत सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। इसलिए पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों की भी अच्छी-खासी संख्या है। ऐसे 76 शहर योजना में शामिल किए गए हैं, जिनकी आबादी पांच लाख से कम है और वे सार्वजनिक परिवहन के उपयुक्त ढांचे से वंचित हैं।

इनमें बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा, हरियाणा के हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, मध्य प्रदेश का सागर, ओडिशा का ब्रह्मपुर टाउन, पटियाला के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार और बंगाल के शहर बहरामपुर, बर्धमान, भाटपारा, हावड़ा, कमरहटी, पानीहटी, राजारघाट गोपालपुर और हिमाचल की राजधानी शिमला शामिल हैं।

6 साल की बच्ची से स्कूल बस में छेड़छाड़

स्वाति मालीवाल बोलीं- 'दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं'

परिवहन विशेष न्यूज

छह साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के चेयनमैन ने अभिभाव पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला. साथ ही बच्ची की पहचान सबके बीच उजागर कर दी.

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना का आरोपी ने एक निजी स्कूल की बस में इस घटना को अंजाम दिया है. हद तो तब हो गई कि 6 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का खुलासा होने के बाद स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने कोई पहल नहीं की. उल्टे पीड़ित बच्ची के माता-पिता से शिकायत वापस लेने का दबाव डाला. अब इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तलब किया है.

दिल्ली महिला आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीड़ित 6 साल की बच्ची दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है. लड़की की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब उनकी बेटी की स्कूल बस ने सोसायटी के गेट पर छोड़ा, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का बैग पेशाब के कारण गीला हो गया था. पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था. उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ 24 अगस्त को स्कूल गई और घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दी.

चेयरमैन ने शिकायत वापस लेने का डाला दबाव

आश्चर्य की बात यह कि इस मामले में 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने को कहा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल के चेयरमैन ने उनकी सोसायटी के लोगों के बीच बच्ची की पहचान उजागर कर दी. अब इस माममे में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी के साथ मामले में हुई गिरफ्तारी की जानकारी भी मांगी है.

POCSO एक्ट में एफआईआर क्यों नहीं?

दिल्ली महिला आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या पुलिस को इस मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है? डीसीडब्लू ने दिल्ली पुलिस से 5 सितंबर तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट भी आयोग को देने को कहा है.

पुलिस आरोपियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "हमें स्कूल में एक सीनियर छात्र द्वारा 6 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला मिला है. ये बहुत गंभीर है. 6 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है. आरोपियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. मामले को दबाने की कोशिश करने वाले स्कूल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

अकेलेपन से नहीं उबर पा रहीं? 5 टिप्स की मदद से खुद को रखें पॉजिटिव, डिप्रेशन एंजाइटी भी रहेंगे दूर

लोगों के बीच रहते हुए भी खुद में अकेलापन महसूस करना आपके मेंटल हेल्थ को काफी प्रभावित कर सकता है. खुद को अगर आप ऐसे हालात से बाहर निकालना चाहती हैं तो कुछ टिप्स की मदद लें.

अकेलापन, हालात नहीं, एक तरह की फीलिंग है जिसमें इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अलग थलग पाता है. यह आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और अगर आप इस इमोशन को सही तरीके से डील ना कर पाए तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की गिरफ्त में आसानी से आ सकते हैं. यही नहीं, अधिक दिनों तक अगर आप इस हालात में रहे तो ये आपके शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करने लगता है. अगर आप भी इस तरह अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप सकारात्मक महसूस कर सकते हैं.

अकेलेपन को ऐसे करें दूर

क्लब या क्लास ज्वाइन करें

वेरीवेल माइंड के मुताबिक, अगर आप खुद को अलग थलग महसूस करें तो जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लें जिसमें आपके जैसे लोग हों. इसके लिए आप अपने आसपास कोई क्लब या हॉबी क्लास ज्वाइन करें. इस तरह आप एक ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे और खुद को अकेलेपन से बाहर निकाल पाएंगी.

इन उपायों से दूर होगी घर की निगेटिव एनर्जी

वॉलेंटियरिंग करें

अगर आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई रहेंगी तो आप बेहतर महसूस कर पाएंगी. इसके लिए आप उन जगहों पर वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं जहां काम कर आप लोगों की मदद कर सकें और दूसरों की जिंदगी को आसान बना पाएं. यह भावना आपके अकेलेपन को दूर करने का काम कर सकती है.

जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन

अमृतसर (साहिल बेरी)

श्री गोपाल मंदिर, गोपाल नगर अमृतसर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन दिनांक 31 अगस्त से 6 सितम्बर 2023 प्रतिदिन सायं 5:30 से रात्रि 8:30 बजे तक किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन इस्कॉन मंदिर अमृतसर के अध्यक्ष श्रीमान इन्द्रानुज जी ने पाँचवें स्कंध की कथा में भगवान ऋषभदेव के अवतार लेने और राज्य त्याग के समय अपने सौ पुत्रों को शिक्षाएं देने का वर्णन किया। मृत्यु के समय जैसा चिन्तन होगा बैसा ही अगला जन्म होगा इसका दृष्टान्त प्रभु जी ने महाराजा भरत के चरित्र से दिया जिनको अंतिम समय हिरण का चिन्तन करने पर अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। छठे स्कंध की कथा में प्रभु जी ने नाम महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे अंतिम समय में अपने पुत्र के एवज में नारायण नाम लेने पर भी पापी अजामिल की यमदूतों से भगवान ने रक्षा की। इसके बाद प्रभु जी ने प्रजापति दक्ष द्वारा नारद जी को श्राप देना और राजा चित्रकेतु की कथा का वर्णन किया जिनको माता पार्वती के श्राप के कारण वृत्रासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा।

सातवें स्कंध की कथा में प्रभु जी ने बालक प्रहलाद की कथा के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति न करने के लिए कई तरह की यातनाएं दी

माहेश्वरी समाज ने तीज का सिंजारा उत्सव मनाया

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। माहेश्वरी समाज की विभिन्न 8 क्षेत्रीय सभाओं द्वारा भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए बड़ी तीज के अवसर पर माहेश्वरी समाज धूमधाम से सिंजारा उत्सव मनाया गया इस अवसर पर समाज की सभी महिलाएं मेहंदी लगाती हैं एवं साय कालीन सिंजारे का उत्सव मनाती है इस बार 8 क्षेत्रीय माहेश्वरी सभाओं द्वारा तीज का सिंजारा उत्सव आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की गई महावीर समदानी ने बताया कि इस बार तीज का सिंजारा विजय सिंह पथिक नगर, आरके आरसी व्यास कॉलोनी, संजय कॉलोनी, आजाद नगर, बसंत विहार, काशीपुरी, शास्त्री नगर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा द्वारा विशेष रूप से उत्सव मनाया गया, विजय सिंह पथिक नगर में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा सिंजारे का आयोजन किया गया, भोपालगंज एवं सुभाष नगर मैं मोहल्ला स्तर पर सिंजारा उत्सव मनाया गया माहेश्वरी समाज में कई वर्षों से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए तीज का सिंजारा धूमधाम से मनाया जाता है जिसके तहत समाज की ओर से दाल बाटी चूरमा विभिन्न मेवाड़ी व्यंजनों के साथ उत्सव को पारंपरिक रूप में मनाया जाता है जिसमें क्षेत्रीय सभाओं के सभी परिवार सम्मिलित हुए इस अवसर पर राधेश्याम चेचानी, कैलाश कोठारी, राधेश्याम सोमानी, ओम गटियाणी, देवेंद्र सोमानी अनिल बांगड़, सत्येंद्र बिरला, सुरेश कचोलिया, अशोक बाहेती ,राम किशन सोनी ,सुशील मरोटीया, राजेंद्र कचोलिया केदार गगरानी ,महावीर समदानी, संजय जागेटीया, मुकेश काबरा, सरिता झवर आदि उपस्थित थे।

क्या आप भारतीय संस्कृति के गौरव को समझते हैं?

1. अंको का अविष्कार भारत में हुआ

2. शून्य का अविष्कार भारत ने किया

3. अंकगणित का अविष्कार पूर्व भास्कराचार्य ने किया

4. बीज गणित का अविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया

5. सर्वप्रथम ग्रहों की गणना आर्यभट्ट ने 499 ई. पूर्व में की

6. भारतीयों को त्रिकोणमिति व रेखागणित का 2,500 ई.पूर्व से ज्ञान था

7. समय और काल की गणना करने वाला विश्व का पहला कैलेण्डर भारत में लतादेव ने 505 ई. पूर्व सूर्य सिद्धान्त नामक अपनी पुस्तक में वर्णित किया

8. न्यूटन से भी पहले गुरूत्वाकर्षण का सिद्धान्त भारत में भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया

9. 3,000 ई. पूर्व लोहे के प्रयोग के प्रभाव वेदों में वर्षित है अशोक स्तम्भ इसका स्पष्ट प्रमाण है

10. 400 ई. पूर्व सुश्रूत (भारतीय चिकित्सक) द्वारा सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया गया

11. विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला के रूप में 700 ई. पूर्व भारत में स्थापित था जहाँ दुनिया भर के 10,500 विद्यार्थी 60 विषयों का अध्ययन करते थे

12. सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने वाले प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने की

13. यूरोपिय गणितज्ञों से पूर्व ही छठी शताब्दी में बोद्धायन ने पाई के मान की गणना की जो की पाइथोगोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है हमारा ज्ञान-विज्ञान एवं इतिहास इतना गौरवशाली एवं समृद्ध है

14. दुनिया का पहला संवत- 'विक्रम संवत' पूरे एशिया से शकों को परास्त करते हुये अवन्ति के चक्रवर्ती सम्राट ₹विक्रमादित्य महान₹ ने प्रवर्तित किया। जो ईसा पूर्व 56 से आरम्भ हुआ। इसका उल्लेख जूलियस सीज़र के रोम के ऐतिहासिक तिथिक्रम में भी है। सम्राट गदाफेरिज के लेख में भी विक्रम संवत का उल्लेख ज्यू ग्रन्थ अनुसार मिलता है इससे विक्रम संवत की विश्व व्यापकता स्पष्ट होती है

15. महान वैज्ञानिक डां.जगदिशचन्द्र बसु ने ही पहला वायरलेस कम्युनिकेशन का अविष्कार किया जो बाद में विकसित होता चला और आज मोबाइल, इण्टरनेट आदि के रूप में विकसित हुआ

16. सूर्य किरण में सात रंग है यह डां. सी. व्ही. रमन ने पहली बार दुनिया को बताया 19 वीं सदी में यह दुनिया ने जाना और scattering of lights के सिध्दान्त पर उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लैकिन उससे भी गर्व और हैरानी की बात है कि ₹तैत्तिरीय संहिता₹ नामक प्राचीन ग्रन्थ को ₹सप्त-रश्मी₹ कहा गया है। यानी तैत्तिरीय संहिता के लेखक ऋषि वैज्ञानिक, सी. वी. रमन से पहले ही उनकी Theory समझ चुके थे और उस ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता थे

17. सबसे पहला अर्थशास्त्र भारत में लिखा गया। कौटिल्य दुनिया के पहले अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाले आचार्य थे

18. दुनिया का पहला संविधान भारत ने ही लिखा राजा मनु इसके रचयिता थे और वेद आधार था इसका नाम मनुस्मृति था। यह राजनितीशास्त्र का पहला महान ग्रन्थ है। अंग्रेजी षड्यन्त्र के तहत मैक्समूलर के हाथो इसे अंग्रेज़ों ने लिखवाकर इसमें तोडमरोड़ की और तथ्यों को बदल दिया

19. नाव का अविष्कार और सोने के सिक्कों का चलन में प्रचलन आर्यावर्त की ही देन है

20. पारा (mercury) बनाने की विधियाँ वैज्ञानिक नागार्जुन एवं महर्षि चरक ने सर्वप्रथम दुनिया को दी

21. एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो आज चीन में भी विकसित है, वह तक भारत की ही देन है

22. बोधिवर्मन की मार्शल आर्ट प्रणाली भारत की ही प्राचीन देन है स्वयं श्रीकृष्ण इसमें निष्णात और पारंगत योध्दा थे उन्होंने इसी के प्रयोग द्वारा कंस के बलाढ्य पहलवान मार गिराये... !!

मुख्यमंत्री गहलोत ने नवग्रह आश्रम की पुस्तक आयुष्मान भव का किया लोकार्पण

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भीलवाड़ा जिले के मोतीबोर का खेड़ा स्थित श्रीनवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चोधरी द्वारा आयुर्वेद, कैंसर उपचार सहित अन्य जानकारियों को लेकर लिखित पुस्तक आयुष्मान भव के पांचवे संस्करण का विमोचन किया।

दो दिन के भीलवाड़ा प्रवास पर आये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस से हेलीपेड़ पहुंचने पर श्रीनवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चोधरी द्वारा लिखित आयुष्मान भव पुस्तक का लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री को आश्रम की गतिविधियों व आयुष्मान भव के बारे में जानकारी दी। राजस्व मंत्री ने बताया कि हंसराज चोधरी उनके भाई है।मुख्यमंत्री गहलोत ने आयुष्मान भव के बारे में हंसराज चोधरी से जानकारी ली तथा नवग्रह आश्रम में रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं व उपचार के बारे में भी पूछा। उन्होंने चोधरी को जयपुर आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में नवग्रह आश्रम जैसे संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करायी जायेगी। हंसराज चोधरी ने मुख्यमंत्री को आश्रम का अन्य साहित्य भी भेंट किया।

रजक बोर्ड के गठन पर बसीटा धोबी समाज ने मुख्यमंत्री गहलोत को दी बधाई

अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। राजस्थान धोबी महासभा के सहसचिव गौतम गहलोत ने जानकारी देकर बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भीलवाडा कार्यक्रम के दौरान धोबी समाज की युवा शक्ति व समाज बन्धुओ द्वारा रजक बोर्ड का गठन होने पर फूलों का गुलदस्ता भैंट कर उनको बधाई दी ।इस अवसर पर राजस्थान धोबी महासभा के सचिव सत्तु अन्छेरिया व समाज के वरिष्ठ नागरिक शम्भु दसलाणियॉ , युवा शक्ति के रामेश्वर , लोकेश बसीटा, नरेश जाडोतिया, अजय पायक, अशोक बसीटा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

भाजपा की दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा बेणेश्वर धाम में भीलवाड़ा से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भाजपा की प्रदेश में निकाली जाने वाली चार परिवर्तन संकल्प यात्राओं में दूसरी यात्रा कि शुरुआत रविवार को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से प्रारंभ होगी जिसमें भीलवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे भीलवाड़ा से सांसद, विधायक, जिला प्रमुख , चेयरमेन, पार्षद, प्रधान ,सरपंच ,पूर्व व वर्तमान पदाधिकारीयो के साथ सैकड़ो पदाधिकारीयो एवं कार्यकर्ता की भागीदारी रहेगी प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन भ्रष्टाचार दलित उत्पीड़न किसान और युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत विशेष प्रकार के रथ पर की जाएगी जो जगह-जगह स्वागत सभा के माध्यम से स्वागत किया जाएगा भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री एवं पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में चलने वाली दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में 19 दिनों में 2433 किलोमीटर 52 विधानसभा तय करेगी। यात्रा भीलवाड़ा में 12 सितंबर को प्रवेश करेगी यात्रा रूट को लेकर मेगा प्लान तैयार किया गया है

भीलवाड़ा जिले से बेणेश्वर धाम जाएंगे ढाई हजार कार्यकर्ता

परिवर्तन संकल्प यात्रा -2 का आगाज बेणेश्वर धाम में होगा जिसमें भीलवाड़ा जिले से लगभग ढाई हजार कार्यकर्ता यात्रा के शुभारंभ पर डूंगरपुर जाएंगे भीलवाड़ा जिले के सभी मंडलों से बसों व प्राइवेट वाहनों द्वारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी बेणेश्वर धाम निकलेंगे।

रथ तैयार ,रात में भी हो सकेगी सभा

बेणेश्वर धाम यात्रा के लिए विशेष प्रकार के रथ तैयार किया गया हैं रथ में आगे जो जगह बनाई गई है उसमें करीब 10 लोग खड़े हो सकते हैं व्रत को इस तरीके से डिजाइन किया गया की रात के समय सभा रैली करने के लिए सामने की ओर छत पर स्पॉटलाइट लगी है रैली में संबोधन की आवाज दूर तक पहुंचे इसके लिए जो उच्च क्षमता के स्पीकर लगाए गए हैं रात के भीतर बैठने के लिए कुर्सियां लगी है मुख्य रथ के अलावा गांव धनिया में जहां यह रथ चलने में असमर्थ होगा वहां अतिरिक्त छोटे रथ काम में लिए जाएंगे।

दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य

परिवहन विशेष न्यूज

रायपुर। देशभर से यहां राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्य से एनओसी लेकर आये ऐसे वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करा लिये है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किये है। ऐसे समस्त वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन कराते हुये 20 सितम्बर 2023 तक संबंधित परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही

किया जा सके। अन्यथा ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

एनआईसी द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे है। जिसके तहत अन्य राज्य के वाहनों को पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी हो रहे हैं। किन्तु राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने के पहले अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का केवल पता परिवर्तन की सूचना दर्ज है, जिसमें से विभिन्न वाहनों का छत्तीसगढ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य के ऐसे वाहन जिनका पता परिवर्तन की सूचना पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी परिवहन कार्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही किया जाना है।

चांद के बाद सूरज पर भारत की लम्बी छलांग, गजब

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी, नई दिल्ली। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुनियां के नख्शे पर सालों से फिसड्डी का दर्जा पाए भारत देश को महज 11 दिन के अंतराल में ही सूरज पर आदित्य एल-1 की सफल उडान भर कर और 23 अगस्त को चांद पर भी अपने अंगदी पांव जमाकर दुनियां भर को हैरत में डाल दिया है। भारत नेअपनी मैराथन दौड के शुरू में धीमें और बाद में लम्बी छलांग लगाकर पहला नंबर का तमगा तो पा ही लिया है। शनिवार 2 सितंबर को आदित्य एल-1 सौलर मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। लॉन्चिंग के ठीक 125 दिन यानि 4 महीने के लंबे सफर को तय करके अपने पांईंट एल-1 तक पहुंचेगा।

इस टार्गेट बिंदू पर पहुंचने के बाद आदित्य एल-1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। बता दें कि आदित्य एल-1 मिशन भारत का पहला सौर मिशन है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य से जुडे कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाला है। इस मिशन से सूरज की बाहरी प्रत कोरोना, कोरोनल मास, इंजेक्शन सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, प्री फ्लेयर और फ्लेयर बाद की गतिविधियां और उनकी विशेषताए, सौर तूफान की उत्पत्ति आदि कारको का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य-एल-1 पांच साल तक रोजाना 1440 तस्वीर भेजेगा। जिसकी मदद से सूर्य के अध्ययन में आसानी होगी। वैज्ञानिको के मुताबिक आदित्य-एल-1, की पहली तस्वीर फरवरी महीने में सामने आ जाएगी। बहरहाल यान के लॉन्चिंग के 4 घंटे बाद आदित्य एल-1, ऑर्बिट में पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि आदित्य-एल-1, यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने ठिकाने तक पहुंचने में 4 महीने का लंबा समय लेगा। जहां ऑर्बिट से सौलर अर्थ सिस्टम में कुल 5 एल पॉईंट लॉगरेज बिंदू है। जहां आदित्य-एल-1 जा रहा है। सबसे दीगर बात है कि पृथ्वी से एल-1 केवल 1 प्रतिशत ही हिस्सा है। आदित्य-एल-1, मिशन नासा के सौर मिशन के मुकाबले कम खर्च आया है। दरअसल इस सौर मिशन में करीब 400 करोड रूपये खर्च हुए हैं। जबकि नासा की ओर से लॉन्च किए गए सौर मिशन में करीब 12300 करोड रूपये खर्च हुए थे।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने की लोगों से अपील, शहर की सुंदरता न करें खराब; सब ने कड़ी मेहनत की है

उपराज्यपाल ने तैयारियों में शामिल सभी एजेंसियों और अधिकारियों के प्रयासों और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने बताया कि तैयारियों को शनिवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए कि जी20 शिखर सम्मेलन जैसे भव्य आयोजन एक सप्ताह के नोटिस में आयोजित किए जा सकें। हमने दो महीनों में इस संबंध में बहुत काम किया गया है।

उपराज्यपाल ने तैयारियों में शामिल सभी एजेंसियों और अधिकारियों के प्रयासों और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने बताया कि तैयारियों को शनिवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

सक्सेना ने अपील की है कि जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में कई स्थायी संपत्तियां बनाई गई हैं, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी शहर के लोगों की है। इसे खराब न करें। हमारा पूरा फोकस शहर की खूबसूरती पर को बढ़ाने पर है।

शिखर सम्मेलन से पहले खर्च किए गए बजट और 'शिवलिंग' आकार के फव्वारे के संबंध में उभरे विवादों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं विवादों में नहीं जाना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि कई कलाकृतियां सीएसआर पहल के तहत दी गई हैं और शहर के सौंदर्यीकरण पर ज्यादा खर्च नहीं किया गया है।

शिवलिंग मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो इसे 'शिवलिंग' कह रहे हैं, वह मूर्तिकार की कल्पना है। देश के कण-कण में भगवान हैं। अगर उन्हें इसमें भगवान दिखता है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बस एक कलाकृति दिखती है। मैं दूसरों की राय पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

CNG के पैसे मांगे तो कार सवार लोगों ने तीन सेल्समैन को पीटा, लाठी-डंडों से की हड्डी-पसली एक

खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में नखड़ौला के पास एक पेट्रोल पंप पर कार में सीएनजी डलवाने आए कुछ लोगों ने पैसे मांगने पर तीन सेल्समैन से मारपीट की। लाठी-डंडों और अग्नि-शामक सिलेंडर से जमीन पर गिराकर पीटा। तीनों मानेसर में निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती हैं। वहीं पंप कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में नखड़ौला के पास एक पेट्रोल पंप पर कार में सीएनजी डलवाने आए कुछ लोगों ने पैसे मांगने पर तीन सेल्समैन से मारपीट की। लाठी-डंडों और अग्नि-शामक सिलेंडर से जमीन पर गिराकर पीटा। तीनों मानेसर में निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती हैं। वहीं पंप कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

जानकारी के अनुसार दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस पर खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में नखड़ौला गांव के पास बने इंडियन आयल के पेट्रोल पंप पर बुधवार रात पौने एक बजे अर्टिगा कार पहुंची। इस पंप पर सीएनजी भी मिलती है। सेल्समैन ने सीएनजी डालने के लिए गाड़ी में सवार सभी लोगों को उतरने के लिए कहा। इस पर लोग बिफर गए, हालांकि सभी नीचे उतर आए।

शराब के नशे मे चूर थे आरोपित

सीएनजी डालने के बाद जब सेल्समैन ने रुपये मांगे तो शराब के नशे में चूर आठ युवकों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हाथापाई की और पास में पड़े लाठी-डंडों से सेल्समैन को पीटने लगे। इसी दौरान दो अन्य सेल्समैन युवकों को वहां से भगाने के लिए अग्नि-शामक सिलेंडर उठाकर लाए और धुआं करने लगे।

आरोपित युवकों ने सिलेंडरों को छीनकर उन्हीं से सेल्समैन पर कई वार किए। पेट्रोल पंप के मैनेजर को भी पीटा। लाठी-डंडों के वार से तीनों सेल्समैन के शरीर में कई फैक्चर हो गए। सिर में भी गंभीर चोट आई। सभी को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा गया। इसके बाद सभी यहां से भाग निकले।

आस पास के लोगों ने दिखाई हिम्मत

पेट्रोल पंप पर तैनात अन्य लोगों ने हिम्मत दिखाकर भाग रहे आरोपितों में से एक युवक को दबोच लिया। इसके बाद फोन से गश्त कर रही पीसीआर वैन को बुलाकर आरोपित युवक को सौंप दिया। इस घटना का वीडियो पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया।

खेड़कीदौला थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में पेट्रोल पंप के मैनेजर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। एक आरोपित को पकड़ा गया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। जांच में पता चला है कि सीएनजी डलवाने के लिए आई कार रेवाड़ी जिले की थी। इस घटना से पेट्रोल पंप पर तैनात अन्य कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।

दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के फंड कट पर फोरम ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा

परिवहन विशेष न्यूज

शिक्षकों की प्रमोशन का एरियर अभी तक नहीं मिला, शिक्षकों की प्रमोशन का एरियर ब्याज सहित भुगतान हो।

नई दिल्ली। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के फंड कट पर चिंता जताई है और उनसे मांग की है कि कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकायों के भुगतान के लिए पिछले महीने 100 करोड़ की जो राशि जारी की है वह अपर्याप्त है। उनका यह भी कहना है कि जो राशि दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से जारी हुई है वह अभी तक कॉलेजों में नहीं पहुंची है। इसलिए सरकार को सभी मदों के भुगतान के लिए कॉलेजों को क्वाटरली राशि जारी करनी चाहिए। उन्होंने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में बताया है कि शिक्षकों की प्रमोशन हुए डेढ़ साल हो चुका है लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए शिक्षकों को एरियर का भुगतान ब्याज सहित दिया जाए।

फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि देखने में आया है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से उनके द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिला। पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेज गहन आर्थिक संकट से जूझ रहे है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के लिए भी कई-कई महीनों इंतजार करना पड़ता है। सरकार जो इंस्टॉलमेंट भेजती है उससे पहले की सैलरी ही मिल पाती है बाकी फिर कई महीनों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिन शिक्षकों की सालभर पहले पदोन्नति हुई थीं उनके एरियर का भुगतान पर्याप्त पैसा न मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है। डॉ.सुमन ने यह भी बताया है कि मेडिकल बिलों का भुगतान, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन, एलटीसी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे जरूरी भुगतान भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं।

डॉ.सुमन ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में इन कॉलेजों का बुनियादी ढांचा भी दयनीय अवस्था में है। उनके अनुसार अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग की हालत खराब है। लैब, क्लास रूम, शौचालय, पीने का पानी, सेमिनार हॉल, गार्डन की स्थिति भी समुचित ग्रांट न मिलने के कारण दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। डॉ.सुमन ने जब तक वेतन, एरियर की समुचित राशि समय पर नहीं जारी होती है और बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होता तब तक दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में सरकार की गवर्निंग बॉडी न बनाएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिस तरह से अन्य कॉलेजों में एडहॉक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति व प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है ठीक उसी तरह से इन कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए रोस्टर पास कर पदों को विज्ञापित करें। उन्होंने बताया है सरकार के भाष्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस ने अपने यहाँ शिक्षकों के पदों को भरने के लिए पहल की है उसी तरह से 11 अन्य कॉलेज भी विज्ञापन जारी कर स्थायी नियुक्ति करें ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय से एडहॉकइज्म समाप्त हो।

डॉ.हंसराज सुमन
चेयरमैन --फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस

कोई धमकी ना दे: 'वो अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए आजाद', दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को फिर मिलाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक साथी के परिवार की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए एक समलैंगिक जोड़े को साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा कि महिला बालिग है और उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय समलैंगिक महिला के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को निर्देश दिया कि वे उसे या उसके साथी को धमकी न दें या उस पर दबाव न डालें। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत का आदेश तब आया जब महिला ने कहा कि वह अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती और अपने साथी के साथ रहना चाहेगी। इसमें कहा गया है कि महिला वयस्क है और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी पक्ष ने उसके आदेश का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएल रिपोर्ट से नया मोड़, लड़की की हत्या से पहले किया था घिनौना काम

बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई की रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग मूकदर्शक बने वारदात को देखते रहे।

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई किशोरी की हत्या मामले को एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद नया मोड़ आया है। नाबालिग की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अलग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। अब पुलिस को दुष्कर्म करने वाले की तलाश है।

दरअसल, बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई की रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग मूकदर्शक बने वारदात को देखते रहे।

किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया।

यह पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोपी 20 साल के साहिल को 29 मई को दोपहर बाद यूपी के बुलंदशहर स्थित उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार किया था।

आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जानकारी दी थी कि नाबालिग और साहिल रिलेशनशिप में थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के बाद पॉक्सो, छेड़छाड़ और एसएसी-एसी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

मामले में दिल्ली पुलिस आरोप पत्र भी कोर्ट में दायर कर चुकी है। लेकिन अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट आई है। इसमें किशोरी के साथ दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज किया गया है।

घटना का सीसीटीवी भी सामने आया

घटना का 90 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया था, जिसमें आरोपी जानवरों की तरह किशोरी पर हमला करते हुए दिख रहा था। वह मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उस पर सीमेंट के स्लैब से उस पर कई बार हमला करता दिखा था।

प्रतिमंडल ने ज्ञात किया कि मणिपुर में लगभग 65,000 लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें से कई शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से 14,000 बच्चे हैं।

उत्तर भारत तक सीमित इस्लामोफोबिया अब दक्षिणी भारत में भी फैल गया है:जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

शम्स आग़ाज़ जामेई

नई दिल्ली: सरकार ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं। ये बिल आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद को इन विधेयकों को लेकर गंभीर चिंता है और समझती है कि ये संशोधन आपराधिक न्यायशास्त्र में वैश्विक रुझानों के अनुरूप नहीं हैं ये बातें जमात ए इस्लामी हिन्द ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने ने कहा कि जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, जमाअत के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी और अब्दुल हलीम फुंद्रेमायुम ने किया। प्रतिमंडल ने ज्ञात किया कि मणिपुर में लगभग 65,000 लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें से कई शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से 14,000 बच्चे हैं। हिंसा में 198 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य को अब तक कितना आर्थिक नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मणिपुर को वस्तुतः जातीय आधार पर विभाजित किया गया है। घाटी के लोग पहाड़ी इलाकों और पहाड़ी इलाक़े वाले घाटी में नहीं जा सकते। जातीयता के आधार पर दंगाइयों द्वारा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में इस्लामोफोबिया की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करती है। और कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्र, विशेष रूप से कस्बों और टियर -2 शहरों में गंभीर प्रकार के भेदभाव का शिकार होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक चिंताजनक और बेहद निंदनीय घटना घटी, जहां एक सात वर्षीय मुस्लिम बच्चे को सहपाठियों ने थप्पड़ मारे। कक्षा में बैठे शिक्षक ने छात्रों को अन्य मुस्लिम छात्रों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां करते हुए हिंसा करने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में उत्तर भारत तक सीमित इस्लामोफोबिया अब धीरे-धीरे दक्षिणी भारत में भी फैल गया है। जिन राज्यों में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां परीक्षा के दौरान मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोके जाने की खबरें सामने आई हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने कहा के हम सितंबर 2023 में नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 43 प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों का स्वागत करते हैं।

गाजियाबाद पुलिस का नया कारनामा, घर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार का किया चालान; फोटो में स्पलेंडर बाइक

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में घर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार का पुलिस ने चालान कर दिया। मोबाइल पर मैसेज आने पर चालान की जानकारी हुई। चालान पर स्पलेंडर बाइक का फोटो लगा है जबकि नाम पता व वाहन नंबर स्विफ्ट डिजायर का है। मामले में टीआई मोदीनगर का कहना है कि तकनीकी कारणों से इस तरह के मामले सामने आते हैं। पीड़ित की शिकायत पर इसमें संशोधन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय
नोटिस
(अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)

सेवा में,
GIRISH GOEL

NO IMAGE AVAILABLE

वाहन संख्या:	UP14D*****	इंजन संख्या:	---------
वाहन अवधि	---------	चेसिस संख्या:	---------
वाहन श्रेणी:	Motor Car(LMV)	वाहन स्वामी का नाम:	G*R*S* *O*L
वाहन पंजीयन की वैधता अवधि:	---------	वाहन स्वामी के पिता का नाम:	SURENDRA KUMAR GUPTA
वाहन स्वामी का मोबाइल:	*******953	वाहन स्वामी का पता:	A-3 GALI NO-1 GURANANAKPURA, MODINAGAR, , Ghaziabad-201204

यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण

चालान संख्या: UP15969423082618441 6

तिथि / समय	स्थान	उल्लंघन का विवरण	शमन शुल्क (रु.)
26-08-2023 18:44:16	530, Nandgram, Ghukna, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201003, India	1: Violation of traffic rules by the driver except the offences mentioned in Section in 184 a, b, d, e, f and without any indication changing the alignment (MV act 1988 S 119 R/W S 177 mentioned in section 184 a,b,d,e,f)	500/-

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है । अत:एव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों

मोदीनगर। गाजियाबाद पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। घर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार का पुलिस ने चालान कर दिया। मोबाइल पर मैसेज आने पर चालान की जानकारी हुई। चालान पर स्पलेंडर बाइक का फोटो लगा है, जबकि नाम, पता व वाहन नंबर स्विफ्ट डिजायर का है।

कई दिन से कार बाहर नहीं निकली

पीड़ति का कहना है कि कई दिन से वे कार लेकर नहीं गए। फिर चालान कैसे हो गया। उन्होंने मामले की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल व यातायात पुलिस के उच्चाधिकारियों से की है। गुरुनानकपुरा कालोनी के गिरीश गोयल के मुताबिक, उनके पास स्विफ्ट डिजायर कार है।

चालान पर स्पलेंडर बाइक की फोटो

उनके मोबाइल पर दो दिन पहले चालान का मैसेज आया। उन्होंने ऑनलाइन चालान चेक किया तो उसपर पांच सौ रुपये रकम लिखी आई, लेकिन चालान पर फोटो स्पलेंडर बाइक का था। गिरीश के मुताबिक, उनकी कार कई दिन से घर में ही थी। इस तरह चालान पूरी तरह गलत है।

उन्होंने इस संबंध में डीसीपी व एसीपी ट्रैफिक को मेल भी किया है। मामले में टीआई मोदीनगर का कहना है कि तकनीकी कारणों से इस तरह के मामले सामने आते हैं। पीड़ित की शिकायत पर इसमें संशोधन किया जाता है।

पहले भी आया ऐसा मामला

इससे पहले जून महीने में भी जिले में इसी तरह का मामला सामने आया था। हरियाणा में नवाबगढ़ के मुस्तफा खान ने थाना गाजियाबाद के कविनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बाइक छह माह से घर पर खड़ी है, लेकिन गाजियाबाद में उसके 14 चालान हो गए हैं। चालान की पड़ताल की तो एक चालान में अजीत का नाम व मोबाइल नंबर लिखा था।

कॉल कर अजीत को बुलाया तो वह बुलेट बाइक के साथ थाने पहुंचा। बाइक के बारे में पूछने पर कहा कि बुलंदशहर के बीबीनगर में रहने वाले उसके साले सुनीत उर्फ सुनील ने तीन साल पहले यह बाइक चलाने के लिए दी थी। सुनील फिलहाल मध्यप्रदेश की आगर मालवा जेल में गांजा तस्करी के आरोप में बंद है।

बाइक की पड़ताल की तो इंजन व चेसी नंबर भी मिटाने का प्रयास किया गया था। बाइक को फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि बाइक कहां से चोरी की गई थी। पुलिस के मुताबिक अजीत को चोरी व फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर पूर्व में कोई केस दर्ज नहीं है।

पुलिस चौकी के सामने लगे मोबाइल टावर से उपकरण चोरी, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र की शनि चौक पुलिस चौकी के सामने चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने एक मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के टावर से उपकरण चोरी कर लिए। नेटवर्क सेवा टॉप होने पर इंजीनियर पहुंचे तो पता चला। साहिबाबाद कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

साहिबाबाद, जागरण संवाददाता। साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र की शनि चौक पुलिस चौकी के सामने चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने एक मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के टावर से उपकरण चोरी कर लिए। नेटवर्क सेवा टॉप होने पर इंजीनियर पहुंचे तो पता चला। साहिबाबाद कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

मोबाइल टावर की देखरेख करने वाली कंपनी के हर्ष ने बताया कि साहिबाबाद के लाजपत नगर में अचानक मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यहां लगने वाला एक उपकरण चोरी हो गया है।

इसकी जानकारी कंपनी के अधिकारियों को दी। फिर साहिबाबाद कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी के पास भी लोग सुरक्षित नहीं है। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है।

अपराध के खिलाफ महिलाओं की शक्ति बनेंगे पिंक बूथ और मोबाइल, सेफ सिटी योजना के तहत शुरू होगी सुविधा

परिवहन विशेष न्यूज

कोई भी अपराध होता है तो महिलाएं थाने व चौकी जाती हैं जहां प्रभारी के साथ अधिकांश पुलिसकर्मी पुरुष ही होते हैं। महिला थाना सिर्फ एक है और यहां सिर्फ पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है। यह समस्या दूर करने के लिए जिले में आज से 20 पिंक बूथ और 20 पिंक मोबाइल शुरू हो रही हैं जिन पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी।

गाजियाबाद। कोई भी अपराध होता है तो महिलाएं थाने व चौकी जाती हैं, जहां प्रभारी के साथ अधिकांश पुलिसकर्मी पुरुष ही होते हैं। महिला थाना सिर्फ एक है और यहां सिर्फ पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है। यह समस्या दूर करने के लिए जिले में आज से 20 पिंक बूथ और 20 पिंक मोबाइल शुरू हो रही हैं, जिन पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी।

पुलिस चौकियों को बनाया पिंक बूथ

सेफ सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने आठ महानगरों में यह सुविधा शुरू की थी और राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 महानगरों में इसे शुरू करने की योजना बनाई है।

गाजियाबाद पुलिस ने अपने स्तर से ही 20 पुलिस चौकियों को पिंक बूथ बना दिया है। हर बूथ पर एक महिला दारोगा प्रभारी और तीन या चार महिला सिपाही व हेड कांस्टेबल तैनात की गई हैं।

चार पहिया पिंक मोबाइल वाला पहला जिला

गाजियाबाद पहला ऐसा जिला है, जहां पिंक मोबाइल के रूप में पुलिसकर्मियों को चार पहिया वाहन यानी कार दी गई हैं। इन पर पुरुष चालक तैनात किए हैं।

स्कूटी सवार पुलिसकर्मी महिला पीड़ितों को अपने साथ नहीं ले जा सकतीं, लेकिन कार सवार पुलिसकर्मी महिला को संबंधित थाने, मामूली रूप से चोटिल होने पर अस्पताल और सुनसान स्थान से सुरक्षित जगह पहुंचा पाएंगीं।

बूथ और मोबाइल पर सभी महिलाओं का पूरा डाटा रखा जाएगा ताकि घरेलू हिंसा के मामले में यह रिकार्ड रहे कि पीड़िता के साथ कब-कब ऐसा हुआ है।

इस तरह होगी मदद

पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि अपराध होने पर महिला जिस भी थाना क्षेत्र में रहती हैं, वहां के पिंक बूथ पर जाकर बता सकती हैं। उनकी शिकायत लेकर पुलिस त्वरित मदद पहुंचाएगी। मुकदमे की जरूरत हुई तो पीड़िता को थाने लेकर जाएगी ताकि रिपोर्ट दर्ज होने में कोई समस्या न हो।

महिलाओं को सुरक्षा और निजता का एहसास दिलाने में पिंक मोबाइल अहम रहेंगी, क्योंकि पीआरवी, पीसी वैन, चीता मोबाइल के साथ अब ये भी अपने-अपने क्षेत्र में घूमेंगी। भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे प्रमुख बाजार, स्कूल कालेज के बाहर ऐसे समय में गश्त करेंगी, जब महिलाओं की संख्या अधिक हो।

जानें, कहां है आपका पिंक बूथ

थाना पिंक बूथ
नगर कोतवाली दूधेश्वरनाथ चौकी
विजय नगर जल निगम चौकी
सिहानी गेट पुराना बस अड्डा चौकी
नंदग्राम नंदग्राम चौकी
कवि नगर सेक्टर-तीन, राजनगर चौकी
मधुबन बापू धाम सेक्टर-23 चौकी
इंदिरापुरम शिप्रा माल चौकी
कौशांबी कौशांबी चौकी
साहिबाबाद मोहन नगर
लिंक रोड महाराजपुर चौकी
शालीमार गार्डन सेंट्रल पार्क डीएलएफ बीट
लोनी लोनी तिराहा चौकी
ट्रोनिका सिटी ट्रोनिका सिटी चौकी
लोनी बार्डर संगम विहार चौकी
अंकुर विहार डीएलएफ चौकी
मसूरी गार्डन एन्क्लेव चौकी
मुराद नगर रेलवे रोड चौकी
मोदी नगर गोविंदपुरी चौकी
वेव सिटी अध्यात्मिक नगर चौकी
क्रासिंग रिपब्लिक बाइपास चौकी

बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से गैराज में लगी आग, कार जलकर हुई राख

साहिबाबाद स्थित इंदिरापुरम कोतवली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-2 रेसीडेंसी अपार्टमेंट में सर्विस के दौरान गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। कार में आग लगने से अपार्टमेंट में धुआं भर गया। कार में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमनकर्मियों की टीम ने अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

गाजियाबाद/साहिबाबाद। साहिबाबाद स्थित इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-2 रेसीडेंसी अपार्टमेंट में सर्विस के दौरान गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। कार में आग लगने से अपार्टमेंट में धुआं भर गया। कार में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि कार में आग बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

गुरुग्राम के ओबेरॉय होटल में रुकेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, 8-10 सितंबर रहेगा नो फ्लाई जोन

दिल्ली में होने वाले जी20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल साइबर सिटी के पांच सितारा होटल ओबेरॉय में रहेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखकर आठ से 10 सितंबर तक पूरा गुरुग्राम नो फ्लाई जोन रहेगा। इस दौरान आठ से 10 सितंबर तक ड्रोन उड़ाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस विशेष रखेगी।

गुरुग्राम। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल साइबर सिटी के पांच सितारा होटल ओबेरॉय में रहेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव को नोडल ऑफिसर लगा दिया गया है।

तीन दिन गुरुग्राम रहेगा नो फ्लाई जोन

वे पूरी व्यवस्था के ऊपर नजर रखेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखकर आठ से 10 सितंबर तक पूरा गुरुग्राम नो फ्लाई जोन रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शिखर सम्मेलन आठ से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें संबंधित देशों के शासनाध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। कई देशों के विदेश मंत्री भी पहुंचेंगे।

8 सितंबर को पहुंचेंगे साउथ कोरिया को राष्ट्रपचति

सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मेहमानों को अलग-अलग कई होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई है। अधिकतर मेहमान दिल्ली के ही विभिन्न होटल में रहेंगे। कुछ के रहने की व्यवस्था एनसीआर के भी होटलों में की गई है। इन्हीं में से एक साउथ कोरिया के राष्ट्र पति को गुरुग्राम के पांच सितारा होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है।

उनके साथ लगभग 100 सदस्य पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखकर सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। होटल दिल्ली सीमा के नजदीक है। इस वजह से गुरुग्राम पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा के ऊपर नजर रहेगी। राष्ट्र पति आठ सितंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम पहुंचेंगे। यहीं से बैठक में भाग लेने के लिए उनका काफिला दिल्ली के लिए रवाना होगा।

परोसे जाएंगे मोटे अनाज के व्यंजन

पांच सितारा होटल में राष्ट्र पति व उनके साथ आने वाले सदस्यों को मोटे अनाज के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इस साल पूरे दुनिया में मोटे अनाज को विशेष रूप से प्रचारित किया जा रहा है। मोटे अनाज के पांच निर्यातक देशों में भारत भी शामिल है।

इसका निर्यात आने वाले समय में बढ़े, इसके लिए डिमांड का होना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार मोटे अनाज का जमकर प्रचार कर रही है। प्रचार के लिए जी-20 बेहतर प्लेटफार्म साबित हो रहा है। सरकार इसका बेहतर उपयोग कर रही है।

आठ से 10 सितंबर तक ड्रोन उड़ाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस विशेष रखेगी। जहां से जिस समय शिकायत मिलेगी, छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ समय से ड्रोन के उपयोग को लेकर आकर्षण बढ़ा है। कई कार्यों में ड्रोन का उपयोग किया जाने लगा है।

डेढ़ साल में बिना टिकट रोडवेज से सफर करते पकड़े गए 3729 यात्री, किराए से ज्यादा देना पड़ा जुर्माना

उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में पिछले करीब डेढ़ साल में 3729 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। गाजियाबाद रीजन में वित्त वर्ष 2022-23 में 2682 व इस साल अप्रैल से अगस्त तक 1047 यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं। फ्री में यात्रा करने के चक्कर में इन लोगों को किराए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा है।

साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पिछले करीब डेढ़ साल में 3729 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। इन यात्रियों से बिना टिकट यात्रा करने पर दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। फ्री में यात्रा करने के चक्कर में इन्हें किराए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा।

परिवहन निगम की टीम बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए बसों की जांच करती है। इसमें यातायात अधीक्षक व सहायक निरीक्षक शामिल होते हैं। गाजियाबाद रीजन में वित्त वर्ष 2022-23 में 2682 व इस साल अप्रैल से अगस्त तक 1047 यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं।

अप्रैल-मई में पकड़े गए सबसे अधिक यात्री

सबसे ज्यादा यात्री बीते साल अप्रैल व मई में पकड़े गए हैं। इसके अलावा निर्धारित से अधिक सामान लेकर जाने के 38 हजार 150 मामले आए हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री 20 किलोग्राम से कम सामान ही बिना टिकट के ले जा सकता है। इससे अधिक सामान लेकर जाने पर टिकट लेना अनिवार्य होता है।

इस तरह लगाया जाता है जुर्माना

बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से उससे किराए के अलावा 500 रुपये या कुल किराए का 10 गुना जुर्माना लगाया जाता है। इनमें से जो भी कम हो होता है, वह यात्री से वसूला जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि यात्री पर पैसे कम होते हैं। इस परिस्थिति में उसके पास जो भी पैसे होते हैं उसके आधार पर ही जुर्माना लगा दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2022-2023 में पकड़े गए यात्री

माह - यात्री
अप्रैल - 336
मई - 318
जून - 247
जुलाई- 219
अगस्त - 201
सितंबर - 186
अक्टूबर - 124
नवंबर - 228
दिसंबर - 210
जनवरी - 208
फरवरी- 188
मार्च - 217

बिना टिकट पकड़े गए यात्री
माह- यात्री
अप्रैल - 199
मई - 215
जून - 207
जुलाई - 182
अगस्त - 244

बसों की जांच कर बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ा जाता है। इसके बाद उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जाती है। - केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक,

मोनू मानेसर समेत अन्य लोगों के विरुद्ध गुरुग्राम में हेट स्पीच के कई केस दर्ज हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने अभी यहां ज्वाइन किया है। ऐसे में पता किया जाएगा कि हेट स्पीच के कौन से मामले दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हेट स्पीच करके निकल जाना आसान नहीं है।

वॉल्वो की यह दमदार इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर चलेगी 530 km, 27 मिनट में होगी चार्ज

वोल्वो अपनी कार सेगमेंट में बेहद अट्रैक्टिव और लग्जरी गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है। इसी सेगमेंट में कंपनी की नई ईवी कार लॉन्च होने वाली है। यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 530 km किलोमीटर तक चलती है। यह बिग साइज कार होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Volvo C40 Recharge 150 kW फास्ट चार्जर से महज 27 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी। इस कार में सेफ्टी के धाकड़ फीचर्स मिलेंगे। यह दमदार बैटरी पैक के साथ आएगी। बताया जा रहा है कि Volvo C40 Recharge एक हाई क्लास कार होगी, जो केवल सिंगल टॉप वैरिएंट में ही आएगी।

एलीट लुक देने के लिए 19-इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील

Volvo C40 Recharge में शौकीनों की फेमस गाड़ी हमर की तरह दिखने वाले बड़े LED हेडलैंप मिल सकते हैं। इसके अलावा कार का एलीट लुक देने के लिए 19-इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलेंगे। कार में स्लोपिंग रूफलाइन वर्टिकल टेल लैंप और इसे अपने सेगमेंट में अलग दिखाने के लिए स्पॉइलर मिलेंगे जो बूट की तरफ माउंट किए गए हैं।

पैनोरेमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

इंटीरियर की बात करें तो इस धांसू कार को पूरी तरह लैदर फ्री किया गया है। इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें पैनोरेमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। Volvo C40 Recharge में 78kWh का दमदार बैटरी पैक मिलता है।

Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग

कार में डुअल इलेक्ट्रक बैटरी सेटअप दिया गया है। यह कार सड़क पर 405 bhp की हाई पावर और 660 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। Volvo C40 Recharge को Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। Volvo C40 Recharge बाजार में Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 को टक्कर देगी।

सुपर लग्जरी कार

जानकारी के अनुसार Volvo C40 Recharge बाजार में 59 लाख रुपये से 60 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर मिलेगी। यह कंपनी की सुपर लग्जरी कार होगी। इसमें सीट एडजस्टमेंट, रियर सीट पर कई लग्जरी फीचर्स मिलेंगे। फिलहाल कंपनी ने इस कार के बारे में अधिक जानकारी शेयर नहीं की है। अनुमान है कि यह धांसू इलेक्ट्रिक कार सितंबर 2023 में लॉन्च कर दी जाएगी।

सात सितंबर को पेश होगी नई टाटा नेक्सन ईवी, जानिए क्या मिलेंगे अपडेट

एमआर और एलआर दोनों मॉडलों के ट्रिम लेवल को आईसीई नेक्सन फेसलिफ्ट में मिलने वाले स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस के अनुरूप रखा जाएगा.

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स, अपनी नेक्सन ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसमें ICE नेक्सन फेसलिफ्ट के समान बॉडी पैनल देखने को मिलेगा. जैसा कि नए टीज़र में देखा गया है, टाटा अपने आईसीई मॉडल की तुलना में नेक्सन ईवी को अधिक अपडेटेड लुक के बाद साथ पेश कर रही है. टाटा 7 सितंबर को 2023 नेक्सन ईवी को पेश करेगी, जबकि इसे 14 सितंबर को 2023 नेक्सन के साथ लॉन्च किया जाएगा. नेक्सन ईवी के कारण ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक लोकप्रियता मिली है. इसके पहले देश में कुछ गिने चुने इलेक्ट्रिक मॉडल ही मौजूद थे. नेक्सॉन ईवी ने अकेले दम पर भारत में ईवी सेगमेंट को बदल दिया और इसे लोकप्रिय भी बनाया.

डिजाइन

अपने ICE मॉडल की तरह, Nexon EV में भी कर्व कॉन्सेप्ट से प्रेरित एक समान डिज़ाइन थीम मिलेगा. वर्तमान नेक्सॉन ईवी का लगभग हर एक डिज़ाइन एलिमेंट इसके आईसीई मॉडल से मिलता जुलता है. लेकिन, अब इन दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलेंगे. इसमें नए एलईडी डीआरएल पैटर्न मिलेंगे, जबकि आईसीई फेसलिफ्ट में एलईडी डीआरएल में स्प्लिट अप्रोच है. हालांकि, Nexon EV के फ्रंट में कनेक्टेड डिज़ाइन LED DRLs की सुविधा मिलेगी. यह नेक्सन आईसीई और ईवी मॉडल के बीच मुख्य अंतर होगा. साथ ही इसमें अन्य कई अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे.

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

नेक्सन ईवी फेसलिफ्ट पावरट्रेन के मामले में मौजूदा मॉडल के समान ही रहेगी. इसमें प्राइम और मैक्स मॉडल के साथ क्रमशः समान 30.2 kWh और 40.5 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा. साथ ही पहले ही जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स भी मिलते रहेंगे. इसकी रेंज भी मौजूदा मॉडल के समान, प्राइम के साथ 312 किमी और मैक्स मॉडल के साथ अधिकतम 453 किमी रहने की संभावना है.

बदलेगा नाम

इसके ICE मॉडल की तरह ही इसके ट्रिम लाइनअप में भी एक ओवरहाल होगा, यानि अब Nexon EV Prime और Nexon EV Max का नाम बदलकर टियागो ईवी के लाइनअप के समान क्रमशः नेक्सन ईवी MR (मीडियम रेंज) और Nexon EV LR (लॉन्ग रेंज) कर दिया जाएगा. फ्रंट में डीआरएल के अलावा, नेक्सन ईवी में अलग डिजाइन के व्हील भी मिल सकते हैं.

फीचर्स

एमआर और एलआर दोनों मॉडलों के ट्रिम लेवल को आईसीई नेक्सन फेसलिफ्ट में मिलने वाले स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस के अनुरूप रखा जाएगा. सनरूफ के साथ एस वेरिएंट और वैकल्पिक किट के साथ + वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ नई 10.25₹ टचस्क्रीन, 10.25₹ फुल डिजिटल और कॉन्फ़िगर करने योग्य इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन, नए टच और टॉगल बेस्ड एचवीएसी कंट्रोल, नए लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी आईसीई मॉडल के समान होंगी. इस कार का मुकाबला हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और एमजी एस ई वी जैसी कारों से होगा।

EV बनाने के लिए लाइसेंस लेने की तैयारी में JSW Group, MG Motors से हाथ मिलाने की प्लानिंग

सज्जन जिंदल (Sajjan Jindal) की अगुवाई वाला जेएसडब्ल्यू ग्रुप (JSW Group) इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने की प्लानिंग कर रहा है. ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है. JSW Group EV सेक्टर में एंट्री करने के लिए MG Motor India के साथ बातचीत भी कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है प्लानिंग.

इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि JSW ऐसे सिंगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है जिसके जरिए कम से कम तीन मिड-साइज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) बनाए जा सकें. Leapmotor इसमें जीनियरिंग से जुड़ी मदद भी करेगी. हालांकि, यह पता नहीं चला है कि JSW कब तक प्रोडक्शन शुरू कर सकता है. इसके अलावा JSW Group की योजना MG Motor की भारत में यूनिट में हिस्सेदारी खरीदने की भी है. MG Motor का मालिकाना हक चीन की SAIC Motor के पास है. देश का EV मार्केट शुरुआती दौर में है. इस मार्केट में Tata Motors की सबसे अधिक हिस्सेदारी है. पिछले वित्त वर्ष में देश में बिक्री कुल कारों में EV की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम थी. Read More – सरकारी नौकरी छोड़ मॉडल बनी ये महिला : लाखों की कमाई के लिए छोड़ा अपना जॉब, करने लगी ये काम '

जिंदल ने कहा, "ईवी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां जेएसडब्ल्यू समूह को जरूर प्रवेश करना चाहिए। भविष्य इसका है और इस क्षेत्र में कदम रखने का यह सही समय है.'' इस मौके पर जिंदल ने शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ चर्चा का बिंदु नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है. दुनिया इस वास्तविकता को सामने आते हुए देख रही है, जबकि दूसरी ओर विरोधाभास यह है कि कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी बढ़ रही है. Read More – Kitchen Hack- किचन का कपड़ा बहुत जल्दी हो जाता है गंदा और चिपचिपा, इस तरह से करें सफाई '

उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों और ऊर्जा संकट से निपटने तथा पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने की जरूरत है. इसके अलावा जलवायु वित्तपोषण को बढ़ावा देना होगा. जिंदल ने साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को न्यायसंगत और समावेशी बनाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की सिफारिश भी की.

ममता सरकार और अदालती फैसले

योगेंद्र योगी

यह निश्चित है कि विपक्षी दल जब तक सार्वजनिक तौर पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर तुष्टिकरण की नीति का त्याग नहीं करेंगे, तब तक एकता के नाम पर देश के मतदाताओं का विश्वास आसानी से हासिल नहीं कर सकेंगे'

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़, भ्रष्टाचार और वोट बैंक के लिए सरेआम तुष्टिकरण जैसी नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जितनी लताड़ खाई है, उतनी देश के किसी अन्य राज्यों की सरकारों ने शायद ही कभी खाई हो। आश्चर्य की बात यह है कि अदालतों से मिली मुकदमों में हार और फटकार के बावजूद ममता सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। ममता सरकार का रवैया संविधान के कायदे-कानूनों का उल्लंघन करना रहा है। विपक्षी दलों ने ममता सरकार की इस प्रवृत्ति पर कभी पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया। सत्ता में होने का बेजा फायदा उठाने की लगातार बढ़ती पुनरावृत्ति पर अदालतों ने अंकुश लगाया है। ममता सरकार का रवैया ऐसा रहा है जैसे पश्चिमी बंगाल भारत के संवैधानिक दायरे से अलग कोई देश हो। नया मामला पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों में भर्ती घोटाले से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य मामलों की तरह इसमें भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थानीय निकाय भर्ती और शिक्षक भर्ती घोटाले में लिंक है। इन दोनों मामले में वो सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने कथित घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने इस दलील को मान लिया कि ये सब बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सीबीआई जांच काफी आगे पहुंच गई है। अब इसमें दखल देते हुए रोकना उचित नहीं है। इससे पहले भी ममता सरकार को भ्रष्टाचार सहित कई दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली लताड़ और हार के बावजूद ममता सरकार के रवैये में कोई विशेष सुधार नहीं आया। सरकार की न तो कार्यशैली बदली और न ही तृणमूल कांग्रेस में कोई तब्दीली नजर आई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के मामले में कहा था कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट एक पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी। उसी लिस्ट में से चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि यह व्यवस्था गलत है।

राज्य सरकार को चयन का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को लेकर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की राज्यों सरकारों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इन मामलों की तरह ही इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह निर्देश राजनीतिक रूप से पारित किया गया था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से याचिका डाली गई थी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली जिलों के रिशरा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। ममता सरकार को कानून को चुनौती देने के साथ भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसे ही एक मामले में सरकार ने कोर्ट का रुख किया, किन्तु शीर्ष अदालत में जाना सरकार के काम नहीं आ सका।

तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुनवाई में दिया, जिसमें हाईकोर्ट के ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को कथित घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल को कैसे देश के बाहर का हिस्सा समझती है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल में फिल्म 'दि केरल स्टोरी' से बैन हटाने के निर्णय से साबित होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। कुछ इसी तरह का रवैया तमिलनाडु सरकार का भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी 'दि केरल स्टोरी' से बैन हटाने का निर्देश दिया था। बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्त्तव्य है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का ये सकारात्मक दायित्व है। इस तरह तो आप समाज में किसी भी 13 लोगों को चुन सकते हैं। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए, जो लोग न देखना चाहें वो न देखें। वे कुछ भी प्रतिबंध लगाने को कहेंगे।

खेल या कार्टून दिखाने को छोड़कर नियमों का उपयोग जनता की सहनशीलता पर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अन्यथा सभी फिल्में इसी स्थान पर खुद को पाएंगी। ममता सरकार शायद यह भूल गई कि बहुमत से सत्ता में आने का मतलब यह नहीं है कि देश की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा सके। कानून को अपनी सुविधा और फायदे के लिए तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता। ममता सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से मिली हार से कोई पाठ पढ़ा होता तो ऐसे मामलों में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। एकता का सुर अलाप रहे विपक्षी दलों को ममता सरकार की कारगुजारी नजर नहीं आ रही। विपक्षी दल ममता सरकार के विभिन्न मामलों में अदालतों से मिली नसीहत और पराजय पर चुप्पी साधे रहे। इनमें भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में भी विपक्षी दलों ने ऐतराज तक नहीं जताया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर हमले करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाने में कसर बाकी नहीं रखी, किन्तु कोर्ट के मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली विफलता पर कभी उंगली तक उठाने की जरुरत नहीं समझी। यह निश्चित है कि विपक्षी दल जब तक सार्वजनिक तौर पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर तुष्टिकरण की नीति का त्याग नहीं करेंगे, तब तक एकता के नाम पर देश के मतदाताओं का विश्वास आसानी से हासिल नहीं कर सकेंगे।

संपादक की कलम से

संसद का 'मास्टर स्ट्रोक' सत्र

संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को ही स्थगित किया गया था। उसके 38 दिन बाद ही मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, तो यह 'मास्टर स्ट्रोक' साबित हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 18-22 सितंबर के 5 दिनों में संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है, लेकिन एजेंडे का खुलासा नहीं किया है। यह असामान्य कार्यशैली है, क्योंकि स्पीकर के साथ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार को संसद सत्र के एजेंडे का खुलासा करना होता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सोच है। विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का निर्णायक, अंतिम सत्र भी हो सकता है। इसके मद्देनजर, यदि 'एक देश, एक चुनाव' का बिल पारित भी किया जाता है, तो वह एकदम पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव बीते कुछ माह के दौरान ही हुए हैं अथवा उन्होंने अपने कार्यकाल का प्रथम वर्ष ही पूरा किया है। क्या संसद से विधानसभाओं की अवधि बढ़ाने या घटाने का संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकता है? हालांकि चर्चाएं हैं कि सरकार महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, आरक्षण के प्रावधान की ओबीसी की केंद्रीय सूची आदि पर नए विधेयक पेश और पारित करा सकती है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 180 सीटें आरक्षित या बढ़ाई जा सकती हैं। मोदी सरकार ऐसा महिला आरक्षण तय करना चाहती है। अधिकतर प्रस्तावित बिलों के मद्देनजर संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिनके लिए कमोबेश दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा। संविधान संशोधन के कुछ और प्रस्ताव भी संभव हैं। 'चंद्रयान-3' भारत की बहुत बड़ी अंतरिक्ष और वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि है।

संसद हमारे होनहार और अनुभवी वैज्ञानिकों की ऐसी सफलता पर एक प्रस्ताव ला सकती है। भारत की 76 साल की स्वतंत्रता के दौरान जी-20 देशों की अध्यक्षता करना और शिखर सम्मेलन आयोजित करना भी अभूतपूर्व उपलब्धि है। संसद उस पर भी तालियां बजा कर प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि मोदी सरकार 'एक देश, एक चुनाव' का विधेयक पेश करती है, तो यह व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल का निर्णय होगा। देश की राजनीति ही बदल सकती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन तो फिलहाल शैशव-काल में है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराना कोई नई व्यवस्था नहीं है। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 में प्रथम चुनाव कराए गए। 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाते रहे। चूंकि 1968 में विधानसभाएं समय-पूर्व भंग की जाने लगीं और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण लोकसभा चुनाव तय समय से पहले कराए गए, नतीजतन व्यवस्था असंतुलित होती गई। हालांकि ओडिशा में आज भी दोनों चुनाव साथ-साथ और सफलता से कराए जाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 2018-19 से अपने इस मिशन की चर्चा संसद में करते रहे हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं की इस मुद्दे पर सहमति भी रही है। अब विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह सामने आ जाएगा, लेकिन क्या चुनाव आयोग, राज्यों के मुख्यमंत्री और सदन, अंततः सर्वोच्च अदालत आदि कई हितधारक और हिस्सेदारों से परामर्श किया गया है? क्या उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है? दरअसल भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने वैश्विक सर्वेक्षण किया है, जिसका निष्कर्ष है कि करीब 79 फीसदी लोग और नेता भारतीय प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। भाजपा इस लोकप्रियता का चुनावी लाभ लेना चाहती है। उसका आकलन है कि यदि साथ-साथ चुनाव होते हैं, तो राज्यों में भी भाजपा को लाभ मिल सकता है।

चर्चा

छिलकों की छाबड़ी : शादी में शगुन भुगतान

बहुत दिनों बाद एक शादी में जाना हुआ। शादी में जाने का मज़ा तभी आता है अगर उचित जगह पर आयोजन हो और पार्किंग आराम से हो जाए। पंडाल के अंदर पहुंचे तो देखा चोपड़ा व शर्मा, राजकुमार के बेटे के वैवाहिक मेले में गोलगप्पे, बिना गिने खाए जा रहे थे। चोपड़ा ने समझाया, चाट वगैरा खा लेनी चाहिए, कहीं गुप्ताजी के बेटे की शादी की तरह खाना नहीं मिला तो घर जाकर चाय के साथ ब्रैड खानी पड़ेगी। तभी सामने से वर्मा अपनी पत्नी व बेटे के साथ आता दिखा। शर्मा बोला, इनको सपरिवार बुलाया होगा, हमें अकेले बुलाया बीवी से गालियां खिलवाने के लिए। हालचाल लेने और देने के बाद वर्मानी, चुनिंदा कपड़े पहन कर आई पहचान की महिलाओं में शामिल हो गई। आजकल ज्यादा बेहतर मेकअप के कारण पहचानने में वक्त लग जाता है। उनका बेटा हाथ में मोबाइल थामे, सामने चुपचाप बैठे मोबाइल की नदी में उतरे युवाओं में बैठ गया। मेहमान आपस में प्रशंसा कर रहे थे, राजकुमार ने बढिया अरेंजमेंट किया है, स्वादिष्ट खाना और जितनी मजऱी ड्रिंक्स। भटनागर बोला, वह टाईम गया जब एक बंदा बुलाने पर एक ही बंदा आता था, कार्ड पर पत्नी और पति का नाम होने पर बच्चे व बुजुर्ग घर में खिचड़ी खाते थे। कार्ड पर सपरिवार लिखा होने पर ही सब जाते थे।

घर में मेहमान होता तो खाना फ्रिज में रखकर आते थे। अब तो पति का नाम हो तो पूरा परिवार टपकता है। कुछ पिछड़े लोग भी हैं जो लिफाफे पर लिखे मुताबिक आते हैं। शर्मा बोला, तभी तो शादियों में खाना कम पड़ जाता है। लोग अपने मेहमानों को भी ले आते हैं, खाते भी ऐसे हैं मानो कई दिन से खाया नहीं। खाना लेते समय कुश्ती जैसी होती है। कुछ लोग पकाने वालों के पास बैठ खाना निबटा लेते हैं। चोपड़ा ने पूछा, यार वर्मे, तुझे विद फैमिली बुलाया राजकुमार ने? नहीं यार, सिर्फ मुझे बुलाया, पत्नी बोली तो मैंने कहा, चलो। कई दिन से कह रही थी हमने बाहर खाना नहीं खाया। मैंने सोचा आज बढिया मौका है। काफी लोगों से मिलना मिलाना भी हो जाएगा और वैरायटी फूड भी एन्जॉय कर लेंगे। बेटा छुट्टी पर आया है, उसे भी ले आया। भटनागर बोला, अब शर्म का जमाना नहीं रहा, लोग शादी में दिया जा रहा शगुन, उसी समय वसूलते हैं। खन्ना बोला, वर्मे शगुन ज्यादा देगा क्या। अरे नहीं, शगुन का स्टैंडर्ड रेट होता है जिसे बढ़ाना लोकहित नहीं। हर जगह सपरिवार जाना, सोशली अच्छा समझता हूं। कुछ बंदे सपरिवार बुलाते नहीं, यह तो उनकी गलती है। सपरिवार पहुंचना मेरी गलती मानी जा सकती है। पत्नी का भी बराबर का हक है, उसे घर पर क्यों छोड़ूं। शर्मा बोला, सोच तो सही है। समाज में कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता तो हम भी सिस्टम के कुत्ते क्यों पालें। लोग शादी में खाना निबटाने व रिश्ते पटाने जाते हैं। जाओ और न खाओ तो जेब नाराज होती है। अब तो शादी बाद में होती, प्रीतिभोज पहले होता है क्योंकि शगुन वसूलना है। वर्मा बोला, गलती हो गई, प्रिंस से माफी मांग लूंगा। सबने कहा, सब चलता है। वर्मा सिर्फ 'शो' कर रहा था। बिफोर आल, उसने खाने से पहले स्वागत गेट पर शगुन भुगतान कर दिया था।

प्रभात कुमार

निखिल शर्मा

शिक्षक दिवस विशेष : अच्छे शिक्षक ही देश के निर्माता हैं

अध्यापक हर स्तर पर अपने सम्मान को उच्चतर बनाने का प्रयास करें, ताकि कोई विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय को आलोचना का अखाड़ा न बनाए

अध्यापकों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अध्यापक ही देश का निर्माता कहा जाता है। समाज में बदलाव, विकास में प्रगति, चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में पहुंचाने और वहां उतारने की इच्छा शक्ति, अच्छा जीवन जीने की कला, शांति, मैत्री, बंधुत्व विश्व में अच्छे शिक्षकों द्वारा ही संभव हो सका है। शिक्षक के मायने जो बच्चों को सिखा सके, समाज को नेतृत्व दे सके। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर कलाम ऐसे शिक्षक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने देश को सीखने व जल्द विकसित होने की भूख पैदा की है। जवान भारत में लाखों विद्यार्थी ऐसे अच्छे अध्यपकों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। शिक्षक के दायरे में केवल बच्चों को किताबी ज्ञान बांटना या फिर सीखने के प्रतिफल को कक्षा कक्ष में उतारना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में जीवन कौशलों का विकास करते हुए उन्हें आधुनिक जीवन के संघर्ष से अवगत कराना, नशे से बचाना भी शामिल है। अध्यापक दिवस पर अध्यापकों से नई उभरती हुई अपेक्षाएं व चिंताएं भी हैं। नई शिक्षा नीति, नई पाठ्यचर्या एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास तुरंत व महत्वपूर्ण ध्यान चाहते हैं। यह उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, विश्व व्यापार संगठन, सूचना एवं संचार तकनीकी, नव शैक्षिक प्रयोग, खुली अधिगम प्रणाली, जीवन कौशलों का विकास आदि विशेषताएं शिक्षकों में विशेष तौर पर अपेक्षित रहेंगी। इसके अतिरिक्त धर्म की शिक्षा, भाषाओं का ज्ञान, मूल्य शिक्षा व इनकी समझ भी अध्यापकों में होना लाजिमी है। अध्यापकों एवं उनके उन्मुखीकरण पर मूल्यवान अनुसंधान किए गए हैं।

यह अध्यापकों के विकास के लिए प्रदेश एवं देश के संदर्भ में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते यह प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हों। किसी भी देश के अध्यापक तथा वहां की शिक्षा नीति पर यह निर्भर करता है कि उस देश का विकास मानव विकास में परिवर्तित हो और विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहां से यह संभव है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापकों के मानकों को बढ़ाने एवं वर्तमान स्थिति में परिवर्तन की कल्पना करती है। शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे पढने व लेक्चर देने के बजाय फैसिलिटेटर और मैंटर के रूप में कार्य करें। अध्यापक कक्षा कक्ष में इस तरह से सिखाएं कि बच्चों के बीच रचनात्मकता, जिज्ञासा, ज्ञान व सूचना की भूख बढ़े। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रचार व प्रसार एवं बच्चों में इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे डिजिटल रूप से भी साक्षर हों। विद्यालय में अध्यापकों की दिनचर्या बच्चों के साथ इस तरह से हो जिसमें उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास एवं कल्याण विकसित हो सके और अध्यापक बच्चों के अंदर एक समग्र विकास की लौ जगा सकें। यह तभी संभव है जब अध्यापकों की पढने व सिखाने में रुचि निरंतर बने।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को उनके ज्ञान और कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, ऑनलाइन कोर्सेज, अन्य सीखने के अवसरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन अध्यापक प्रशिक्षण में अच्छे प्रशिक्षकों की कमी तथा प्रशिक्षण को कक्षा कक्षा तक ले जाने से लेकर कक्षा कक्ष में उतरने तक कार्यक्रम की

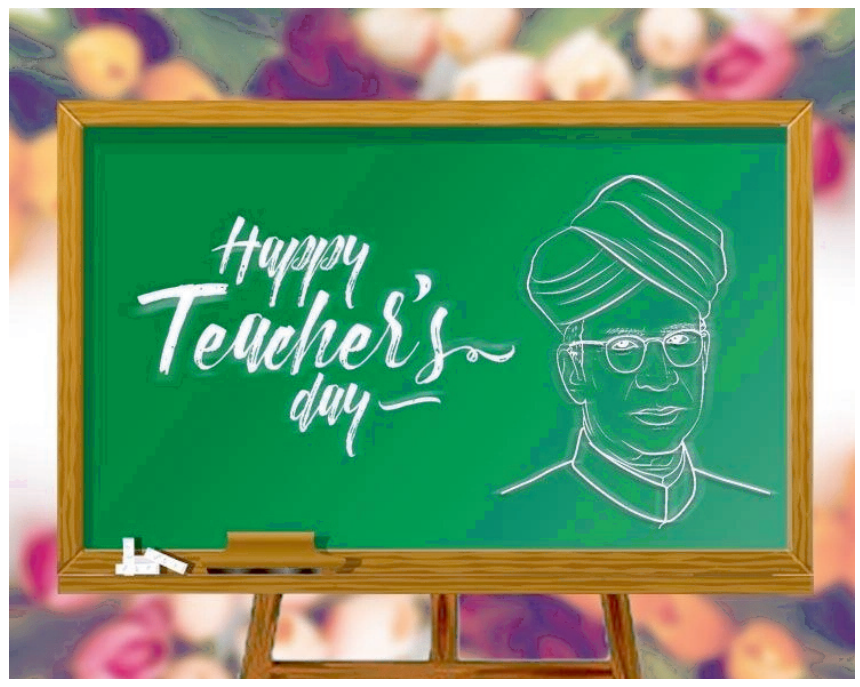

कमी तथा निगरानी में लचर व्यवस्था हमें नार्वे एवं फिनलैंड जैसे विकसित देशों से पीछे धकेलती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लक्जमबर्ग में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पानी वाले शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड हैं जहां शिक्षकों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और वो अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इन देशों के अध्यापकों के पढ़ाने और सिखाने के तरीके भी भिन्न हैं। यहां अध्यापक विद्यालय व कक्षा कक्ष में जाने से पहले पूरी तैयारी करते हैं, या तो स्कूल बोर्डिंग होते हैं या फिर अध्यापक को बच्चों से पहले आकर पढ़ाने की कक्षा कक्ष में तैयारी करनी होती है। इसीलिए उनका आदर सम्मान बरकरार है। रविंद्र नाथ टैगोर ने बरसों पहले कहा था कि एक दीपक दूसरे दीपक को जला ही नहीं सकता, जब तक कि वह खुद न जल रहा हो। अनुसंधान व ज्ञान रहित अध्यापक का पाठ बच्चों के दिमाग के ऊपर ज्ञान लादने का ही कार्य कर सकता है। उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं बना सकता। पिछले दो दशकों में पढने पढ़ाने की विभिन्न विधाओं में परिवर्तन आए हैं और अभी भी प्रयास जारी हैं। देश भर में लाखों शिक्षक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। क्या वे सभी शिक्षक शिक्षा को बच्चों के व्यावहारिक जीवन में उतारने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं। जैसे-जैसे विकास, विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ा है तथा प्रभावित हुआ है, घर से लेकर विद्यालय तक परिवर्तन आए हैं। इंटरनेट, गाड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरएक्टिव बोर्ड सरीखी आधुनिक सहूलियतों से कक्षा कक्ष एवं पढने के तरीकों में बदलाव आवश्यक है। बाहरी परिवर्तन के समकक्ष अपने विद्यालय एवं कक्षा कक्ष, अध्यापकों की सोच, उनके ज्ञान, सूचना, विवेक, सशक्तिकरण व पढ़ाने के मानक स्तरों में भी सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा बढ़ी है। ढांचागत विकास के साथ मानव विकास को प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसलिए भूमंडलीकरण के इस दौर में शिक्षक को अपना सशक्तिकरण करना आवश्यक है, नहीं तो वह अपनी कक्षाओं में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की साख विश्व पटल पर उभर कर सामने आई है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु-शिष्य की परंपरा का बहुत अधिक महत्व रहा है। हमारी संस्कृति के निर्माण में गुरु-शिष्य एवं समाज का योगदान अधिक है। यह शिक्षक ही है जो मनुष्य को इंसान बनाता है। हाल ही में ऊना जिले में विद्यार्थी का प्रधानाचार्य से अभद्र व्यवहार अच्छे अध्यापकों को टीस पहुंचाने वाला है। विद्यालय और अध्यापकों को अपनी गरिमा उच्च स्थान पर रखने की आवश्यकता है। अध्यापक हर स्तर पर अपने सम्मान को उच्चतर बनाने का प्रयास करें, ताकि कोई विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय को आलोचना का अखाड़ा न बनाए और विद्यालय की आस्था और सम्मान कम न हो। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देना व शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

चिंतन विचार

उच्च शिक्षा की कसौटी पर

औचित्य और अनुचित के बीच यूं तो महीन सा फर्क भी काफी सताता है, फिर भी सियासत के छबील अपनी खुशामद में संसाधनों की बेकद्री करते रहते हैं। हिमाचल में औचित्य को साबित किए बिना राजनीति ने ऐसी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी कि लगातार सरकारों ने प्रदेश के सिर पर ऐसी विफलताओं की परिभाषा को स्थायी स्वरूप दे दिया। ऐसे में अनुचित की दुरुस्ती को यहां अपराध मान लिया या औचित्यहीनता के समानांतर ऐसे अनेक फलसफे चुन लिए। ताजातरीन उदाहरण मंडी में स्थापित किए गए एसपीयू विश्वविद्यालय के औचित्य को लेकर सामने आ रहा है, जहां उच्च शिक्षा के प्रबंधन की उचित कसौटी तय हो रही है। जिस तेजी से मंडी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उससे स्थापित शिक्षण की परंपराएं भी चकित थीं। उस दौर की प्राथमिकता में नए विश्वविद्यालय को दौड़ाने की हर संभव कोशिश हुई और शिक्षा अपने बंटवारे की सतह पर हतप्रभ थी। चंद दिनों की मुनादी ने शिमला विश्वविद्यालय के अस्तित्व को इतना हलाल किया कि प्रदेश के कई बड़े महाविद्यालय भी चीख उठे। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ। जब हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय बना, तो प्रदेश के इंजीनियरिंग व बीएड कालेज उखड़ रहे थे। जब मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही थी,तो अधिकांश सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय उचित फैकल्टी के लिए तरस रहे थे। यह तो गनीमत है कि संस्कृत और डिजीटल विश्वविद्यालयों की खेप उतरी नहीं, वरना हिमाचल का किरदार तो आकाश में झंडों की तरह सिर्फ हवा के दम पर फहराना चाहता है। बहरहाल मंडी विश्वविद्यालय को ऐसी सीमा रेखा पर खड़ा किया जा रहा है, जिसे आगे सिर्फ तीन जिलों की शिक्षा की अमानत मिलेगी। भविष्य में मंडी, कुल्लू व लाहुल-स्पीति के कालेज ही इस विश्वविद्यालय के औचित्य को सिद्ध करेंगे। इसे हम अनुचित को सही करना मानें या औचित्य के हिसाब से देखें, लेकिन कुछ तर्क हमेशा ऐसे फैसलों के पक्ष तो कुछ विपरीत खड़े रहते हैं। जाहिर है मंडी विश्वविद्यालय को परिपक्वता हासिल करने के लिए कुछ समय लगेगा और इसी के साथ शिमला विश्वविद्यालय के पास अपने अतीत के संदर्भों को गांठने का अवसर रहेगा। शिमला बनाम मंडी विश्वविद्यालयों की होड़ ने सत्ता का नजरिया और शिक्षा के प्रति गंभीरता का आकलन किया है। शिमला विश्वविद्यालय से मंडी विश्वविद्यालय की उत्पत्ति से करीब चार दशक पूर्व ही धर्मशाला में विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र स्थापित हो चुका था, लेकिन इस संस्थान को राजनीति निगल गई। इसी तरह धर्मशाला में आया केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीतिक हिस्सेदारी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अपनी हद मुकर्रर करता रहा। जदरांगल की प्रस्तावित जमीन के बदले राज्य सरकार को तीस करोड़ जमा कराने हैं, लेकिन शिक्षा की दीवारों पर इसके हक में पोस्टर नहीं लगे। यह दीगर है कि दो या इससे कम संख्या वाले 117 प्राथमिक व 26 मिडल स्कूल सरकार को बंद करने पड़े हैं। अभी कई संस्थान डिनोटिफाई होकर अपने औचित्य की जंग लड़ रहे हैं। हिमाचल का राजनीतिक इतिहास हमें बार-बार सचेत कर रहा है कि औचित्यहीन फैसलों के कारण प्रदेश ने अपने आर्थिक संबल तोड़ डाले हैं। कितने ही औचित्यहीन स्कूल, कालेज, चिकित्सालय, दफ्तर तथा सरकारी उपक्रम संसाधनों की बर्बादी के चिडियाघर बने हुए हैं, जहां जनता सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरक्की में राज्य की लाचारी का तमाशा देख रही होती है। हम भी इस लाचारी का तमाशा बन जाते हैं जब तथाकथित स्नातकोत्तर कालेजों में शिक्षा ग्रहण करके भी योग्यता के बाजार में असफल होते हैं। हमारे चिकित्सा संस्थान तो जिंदगी से बेरहम सौदेबाजी में हर मरीज को तमाशा बना देते हैं और जब पीजीआई चंडीगढ़ के डाक्टर पूछते हैं कि हिमाचल का चिकित्सा विभाग हर दिन मरीजों को रैफर करके आखिर क्या कर रहा है, तो यह प्रदेश का तमाशा है। आखिर हम बतौर राज्य कर क्या रहे और कहां है हमारा औचित्य। इसलिए अगर सुक्खू सरकार मंडी विश्वविद्यालय में अनुचित देख रही है, तो इसी धार पर अन्य विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों के औचित्य पर पूरी ईमानदारी से और भी फैसले लेने होंगे, वरना कल कोई और आकर किसी अन्य संस्थान के औचित्य को गौण कर देगा।

औंधे मुंह गिरा पड़ा था रतन टाटा की इस कंपनी का शेयर, अब स्टॉक खरीदने की मच गई लूट, तूफानी तेजी से बढ़ रहे भाव

शेयर बाजार में अगर सही कंपनी के शेयरों में निवेश किया जाए तो शानदार रिटर्न जरूर मिलता है। ऐसा ही एक शेयर टाटा ग्रुप की कंपनी का है। यह कंपनी टाटा कॉफी है। पिछले कई महीनों से टाटा कॉफी के शेयर सुस्त पड़े हुए थे। अब टाटा कॉफी के शेयरों में बंपर उछाल देखा जा रहा है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। टाटा ग्रुप (Ratan Tata) की कंपनियों ने शेयरों ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अब टाटा ग्रुप (Tata Group) की एक कंपनी के शेयर में बंपर तेजी देखी जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफी के शेयरों में तूफानी उछाल आया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर तीन फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 258.80 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था। यह इस शेयर का 52 सप्ताह का हाई लेवल भी है। यह शेयर 251.40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। टाटा कॉफी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। कंपनी का मार्केट कैप 4695.41 करोड़ रुपये है।

सुस्त रही रफ्तार

टाटा कॉफी के शेयरों के रिटर्न को देखें तो इसकी रफ्तार सुस्त रही है। पिछले छह महीनों में शेयरों ने 20 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं साल दर साल के आधार पर इस शेयर ने 16 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब शेयरों में अच्छा उछाल देखा जा रहा है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में शेयर और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बता दें कि टाटा कॉफी लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसे पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह एशिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है।

कंपनी के नतीजे

बता दें कि अभी हाल ही में कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में 5 फीसदी की गिरावट रही है। यह 62.06 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल की समान अवधि में इसका प्रॉफिट 65.49 करोड़ रुपये था। हालांकि टाटा कॉफी की कुल आय बढ़ी है। यह बढ़कर 707.93 करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 666.05 करोड़ रुपये थी।

महात्मा गांधी के विचारो से प्रेरित है तेलंगाना मॉडल, सीएम केसीआर ने कहा- देश के लिए बना मार्गदर्शक

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना मॉडल देश के लिए एक मार्गदर्शक जैसा बन गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का सपना भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन को अपनाकर ही संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि राज्य समावेशी और व्यापक विकास मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेलंगाना देश के लिए एक मर्गदर्शक जैसा बन गया है।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekar Rao) ने कहा कि 'तेलंगाना मॉडल' देश के लिए एक मार्गदर्शक जैसा बन गया है। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों पर कहा कि महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' की प्रेरणा ने उन्हें राज्य में रायथु बंधु (Rythu Bandhu) और पल्ले प्रगति (Palle Pragathi) जैसे कई ग्राम आधारित कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

राज्य की कल्याणकारी योजना गांधी विचारधारा से प्रेरित

सीएम केसीआर ने शुक्रवार को हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (HICC) में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवलु (Swatantra Bharata Vajrotsavalu) के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित है।

तेलंगाना पर क्या बोले केसीआर?

उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का सपना भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन को अपनाकर ही संभव हो पाया। हालांकि, इस दौरान कुछ ताकतों ने कहा था कि यह एक हिंसात्मक आंदोलन है। उन्होंने कहा

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के गठन के बाद मैंने साफ-साफ कहा था कि तेलंगाना के लिए होने वाला आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगा। हालांकि, कई लोग मुझसे इस बात को लेकर सहमत नहीं थे, लेकिन इस बार पर सभी राजी हो गए थे कि मैंने जो भी रास्ता चुना था वह सही था और सभी ने इसके लिए मेरा समर्थन किया था। मैंने टीआरएस के गठन के दौरान ही फैसला कर लिया था कि इस आंदोलन में कुछ भी हो जाए हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है।

सितंबर की इन तारीखों को कर लें याद, ये काम निपटाने का है अंतिम मौका, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने कई काम निपटाने की अंतिम तारीख है। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सितंबर महीने की इन जरूरी तारीखों को जरूर नोट कर लें। कई जरूरी काम निपटाने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ये काम सीधे आपके रुपयों से जुड़े हुए हैं। यहां हम आपको सितंबर में सभी जरूरी कामों की पूरी लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं।

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने कई काम निपटाने की अंतिम तारीख है। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सितंबर महीने की इन जरूरी तारीखों को जरूर नोट कर लें। कई जरूरी काम निपटाने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ये काम सीधे आपके रुपयों से जुड़े हुए हैं। यहां हम आपको सितंबर में सभी जरूरी कामों की पूरी लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जिससे आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

आधार फ्री अपडेट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मुफ्त आधार अपडेट को 14 जून से 14 सितंबर 2023 तक के लिए तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में आप अब 14 सितंबर तक फ्री में अपने आधार डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार में किसी भी तरह के बदलाव के लिए पैसे देने पड़ेंगे।

पैन आधार लिंक

स्मॉल सेविंग स्कीम खाताधारकों के लिए 30 सितंबर 2023 तक आधार-पैन को लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो सकता है। खाता शुरू करने क लिए छह महीने के अंदर नए यूजर्स जो निवेश करना चाहते हैं या छोटी बचत योजना शुरू करना चाहते है, उन्हें अपना आधार नंबर जमा करना होगा।

नोट बदलने का अंतिम दिन

आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोट को जमा करने या बदलने के लिए चार महीनों का समय दिया था। 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है। आप 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर दो हजार रुपये के नोट को जमा कर सकते हैं।

अमृत महोत्सव योजना

आईडीबीआई की 375 दिनों की अमृत महोत्सव एफडी योजना के तहत बैंक सामान्य ग्राहकों, एनआरई और एनआरओ को 7.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक 7.60 फीसदी ब्याज की पेशकर कर रहा है।

स्पेशल एफडी स्कीम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई वीकेयर में निवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। जो सीनियर सिटीजन्स इसमें निवेश करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक अपना पैसा लगा सकते हैं। इस एफडी में सीनियर सिटीजन्स 7.50 फीसदी के हिसाब से ब्याज दर हासिल कर सकते हैं।

दिवालिया होने की कगार पर रसना! NCLT लेगा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

परिवहन विशेष न्यूज

एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी मंजूर कर ली है। यह मामला 71 लाख रुपये का है। भारत रोड कैरियर नाम की कंपनी ने दिवालियापन की अर्जी लगाई थी। यह मामला कोरोना महामारी से पहले का है।

नई दिल्ली। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना (Rasna) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रसना के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी मंजूर कर ली है। यह मामला 71 लाख रुपये के माल ढुलाई न चुकाने से संबंधित है। भाड़ा नहीं चुकाने पर भारत रोड कैरियर (Bharat Road Carrier) नाम की कंपनी ने दिवालियापन की अर्जी लगाई थी। लॉजिस्टिक फर्म के मुताबिक, ब्रेवरेज कंपनी पर उसका 71.3 लाख रुपये बकाया है। कंपनी के मुताबिक, यह मामला कोरोना महामारी से काफी पहले का है। जब उसने रसना को कई सामान भेजे थे, जिसकी इनवॉइस अप्रैल 2017 से अगस्त 2018 के बीच बनी थी।

कोर्ट में पेश नहीं हुई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में रसना ने अपने बचाव में कहा है कि नवंबर 2018 में भारत रोड कैरियर के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला दायर किया था। जिसे अहमदाबाद के कॉमर्शियल कोर्ट में दायर किया गया था। मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। लेकिन लॉजिस्टिक फर्म मीडिएटर के सामने पेश नहीं हुई। कॉमर्शियल कोर्ट ने 30 अप्रैल 2019 को नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब दाखिल करने की तारीख तक भी कंपनी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई थी।

इस तरह पड़ा नाम

अमीर को या गरीब रसना से सबके गले की प्यास बुझाई है। रसना ने लोअर मिडिल क्लास को एक सस्ता कार्बोनेटेड ड्रिंक उपलब्ध कराया। रसना समूह के संस्थापक अरिज पिरोजशा खंबाटा ने साल 1976 में ऐसे ड्रिंक तैयार किए जो झटपट बन जाते थे। उन्होंने एक ऐसी ही यूनिक रेडी-टू-सर्व कांसन्ट्रेट सॉफ्ट ड्रिंक बनाई और नाम रखा 'जाफे'। यह अलग तरह का नाम होने के कारण यह लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलने का फैसला लिया।

आय में आई कमी

साल 1979 में ड्रिंक का नाम बदलकर 'रसना' रखा जिसका मतलब होता है जूस। साल 2009 में रसना ने सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में 93 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल कर ली। कंपनी ने कई फ्लेवर्स एड किए। साल 2011 में कंपनी का कारोबार 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि बीते वक्त में कंपनी की आय में कमी आई है।

SC से ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष को राहत धर्म परिवर्तन मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष को जबरन धर्म परिवर्तन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मैथ्यू सैमुअल और अन्य द्वारा दायर अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दे दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मैथ्यू सैमुअल और अन्य द्वारा दायर अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। इस नोटिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक

पीठ ने कहा, ₹विशेष अनुमति याचिका के साथ ही निर्देशों के लिए अंतर्वर्ती आवेदन (Interlocutory Application) पर नोटिस जारी करें। इस दौरान पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला फतेहपुर, यूपी में पंजीकृत एफआईआर संख्या 224/2022, 54/2023, 55/2023 और 60/2023 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।₹

हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई रद्द करने से किया था इनकार

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया और एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने पहले राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर में सैमुअल और अन्य के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

कई धाराओं के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की शिकायतें मिलने के बाद सैमुअल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 के साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

कभी अमेरिका में हुए थे नस्लीय भेदभाव के शिकार, फुमियो किशिदा की मेजबानी को तैयार है भारत

G-20 Summitऐसा कहा जाता है कि जापान और भारत के बीच दोस्ती और आदान-प्रदान छठी शताब्दी में शुरू हुआ था जब बौद्ध धर्म जापान में लाया गया था। बौद्ध धर्म से निकली भारतीय संस्कृति का जापानी संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और यही जापानी लोगों की भारत के प्रति निकटता की भावना का स्रोत है। इसी निकटता को बढ़ाने में G-20 सम्मेलन एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

नई दिल्ली। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में दुनियाभर के 40 से ज्यादा देश और उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में इस भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 9-10 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। भारत में इसकी तैयारी जोरशोर से की जा रही है। अलग-अलग देशों के कई दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों की मेहमान नवाजी के लिए भारत तैयार है। G20 के इस अध्यक्षता की वजह से भारत को लेकर कहा जा रहा है कि इससे देश को भविष्य में काफी फायदा मिलने वाला है।

इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई दिग्गज भारत के सरजमीं पर कदम रखने वाले हैं जिसके लिए भारत पूरी गर्मजोशी से 'वसुधैव कुटुम्बकम' की विचारधारा के साथ G20 के इस सम्मेलन में सभी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। यह अपनेआप में एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। इस पल का भारत को बेसब्री से इंतजार है जब राष्ट्रपति बाइडेन राजधानी दिल्ली पहुचेंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

वहीं इन सभी मेहमानों के लिस्ट में शामिल हैं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री का इसी साल यह दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले मार्च 2023 को पीएम किशिदा भारत के दौरे पर आए थे। मार्च के दौरे के बाद फुमियो किशिदा के भारत के इस दूसरे दौरे को लेकर भारत बहुत ही आशावान है।

कौन है फुमियो किशिदा?

फुमियो किशिदा जापान के 64वें प्रधानमंत्री हैं। किशिदा 4 अक्टूबर 2021 से जापान के प्रधानमंत्री के पद पर हैं।

सितंबर 2021 में, किशिदा को रूढ़िवादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। फुमियो किशिदा शिंजो आबे सरकार के दौरान 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। पीएम फुमियो किशिदा जब छह साल के थे तब अपने पिता के काम के कारण अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क गए थे। किशिदा क्वींस के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की जहां उन्हें जापानी होने के कारण कई बार ताना मारा गया। जब भी वह बाथरूम जाया करते तो बच्चे उनपर चिल्लाते थे और वह अक्सर भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के शिकार बना करते थे।

आदित्य-L1 क्यों? क्यूबेक की उस घटना में छिपा है जवाब जब एक झटके में कनाडा के पूरे राज्य की हो गई थी बत्ती गुल

परिवहन विशेष न्यूज

चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-एल1 (ISRO Mission Sun) को शनिवार को लॉन्च किया। सूर्य मिशन का उद्देश्य सूरज से जुड़े रहस्यों की गुत्थी सुलझाना है। सूरज पर होने वाली गतिविधियां धरती को प्रभावित कर सकती हैं।

नई दिल्ली। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर (Chandrayaan 3 Mission) उतारकर इतिहास रचने के बाद भारत ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन (India's First Solar Mission) 'आदित्य-एल1' को सफलता से लॉन्च कर दिया है। इस मिशन (Aditya-L1 Mission news) का मकसद सूर्य से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाना है। आखिर सूर्य मिशन जरूरी क्यों है? सूरज का अध्ययन करना धरती पर रह रहे लोगों के लिए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी जरूरत ही क्या है? हो सकता है कि इस तरह के सवाल आपके जेहन में भी आते हों या आप किसी अन्य के ऐसे सवालों से होकर गुजरे हों। इसका जवाब यही है कि सूर्य मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक अध्ययन की कवायद नहीं है, ये मानवता की बड़ी सेवा भी है। ये मानव के अस्तित्व, धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। सूर्य का अध्ययन, उसके रहस्यों के समझने के पीछे एक बड़ी वजह सूरज का धरती पर पड़ने वाला नुकसानदेह असर है। सूरज पर सौर तूफान (Solar Storm and Flares) आते रहते हैं। इनसे सौर ज्वालाएं निकलती हैं। अगर ये सौर ज्वालाएं धरती की तरफ बढ़ती हैं तो ये बड़ी तबाही ला सकती हैं। करीब 34 साल पहले (The Great Canadian Backout 1989) कनाडा के एक राज्य में घटी घटना के जरिए सूर्य मिशन की अहमियत को समझा जा सकता है।

जब अचानक हुई थी बत्ती गुल, बंद हो गई मेट्रो, एयरपोर्ट भी ठप

कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 1989 में घटी घटना ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह सूरज पर हो रही गतिविधियां धरती पर उथल-पुथल मचा सकती हैं, जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। 13 मार्च 1989 को कनाडा का समूचा क्यूबेक प्रांत अंधेरे में डूब गया। अचानक बत्ती गुल हो गई। लाखों लोग जहां-तहां अंधेरे में कैद हो गए। कोई ऑफिस में तो कोई घर में। कोई अंडरपास में घुप्प अंधेरे में फंसा था तो कोई अचानक रुक चुके एलिवेटर पर फंसा था। स्कूल बंद हो गए। दुकान, शो रूम, बिजनस सब ठप। मॉन्ट्रियल मेट्रो बंद हो गई, डोरवल एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। 12 घंटे तक बिजली गायब रही। वैसे तो उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में हर साल ब्लैकआउट यानी बत्ती गुल होने की सैकड़ों घटनाएं होती हैं। लेकिन ये घटना अलग थी। क्यूबेक ब्लैकआउट की वजह सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नैशनल ऐरोनॉटिक्स ऐंड स्पेस ऐडमिनिस्ट्रेशन' (NASA) ने बताया कि ब्लैकआउट की वजह सूरज पर हुई घटना है। नासा ने इसकी पूरी कहानी बताई।

रेडियो सिग्नल भी हो गया जाम, रूस का हाथ माना गया मगर हकीकत कुछ और निकली

10 मार्च 1989, शुक्रवार को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सूरज पर एक ताकतवर विस्फोट का पता चला। कुछ ही मिनटों में सूरज के मैग्नेटिक फोर्सेज ने अरबों टन गैस छोड़ा। एक ही वक्त पर हजारों परमाणु बम विस्फोट जितना ताकतवर था वो सौर विस्फोट। विस्फोट से पैदा हुई विशाल गैस बादलों की शक्ल में तेजी से सीधे धरती की तरफ बढ़ीं। 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से। सौर ज्वालाओं की वजह से शॉर्ट-वेव रेडियो बाधित हो गईं। यूरोप में रेडियो सिग्नल जाम हो गया। रेडियो तरंगों के जाम होने को शुरुआत में रूस की करतूत मानी गई लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी।

दो दिन बाद यानी 12 मार्च 1989, सोमवार को सोलर प्लाज्मा वाला विशाल बादल आखिरकार धरती के चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया। सोलर प्लाज्मा विद्युत आवेशित कणों वाली गैस होती हैं। इस जियो-मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी भू-चुंबकीय तूफान की वजह से जो चुंबकीय विक्षोभ हुआ या मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हुआ, वह बहुत ताकतवर था। इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में जमीन के नीचे इलेक्ट्रिकल करेंट पैदा हो गई। 13 मार्च को तड़के पौने 3 बजे के करीब इस इलेक्ट्रिकल करेंट ने क्यूबेक के पावर ग्रिड को ठप कर दिया और अचानक पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया।

अमेरिका में भी दिखा था असर

ऐसा नहीं था कि उस सौर तूफान का असर सिर्फ कनाडा के क्यूबेक राज्य में ही पड़ा। अमेरिका में भी न्यू यॉर्क, न्यू इंग्लैंड जैसे कुछ इलाकों में भी लगभग उसी वक्त बिजली सप्लाई बाधित हुई थी। लेकिन क्यूबेक जैसा असर नहीं दिखा।

अंतरिक्ष में भी इसका असर दिखा। कुछ सैटलाइट कई घंटों तक कंट्रोल के बाहर हो गए। नासा के टीडीआरएस-1 कम्यूनिकेशन सैलटलाइट मे 250 से ज्यादा गड़बड़ियां आ गईं। स्पेस शटल डिस्कवरी में भी रहस्यमय समस्याएं पैदा हुईं। हालांकि, सौर तूफान थमने के साथ ही ये गड़बड़ियां भी रहस्यमय ढंग से दूर हो गईं।

उसी साल, 16 अगस्त को एक अन्य सौर तूफान की वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सभी तरह की ट्रेडिंग बंद हो गई।

इस साल अप्रैल में हिंद महासागर में रेडियो सिग्नल हो गए थे फेल

इस साल अप्रैल में भी सौर ज्वालाओं की वजह से हिंद महासागर के ऊपर शॉर्ट वेव रेडियो सिग्नल ठप हो गए थे। हालांकि, ये क्यूबेक ब्लैकआउट की तुलना में बहुत ही छोटी घटना थी। हिंद महासागर के ऊपर शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट की वजह M क्लास की सौर ज्वालाएं थीं। ये मध्यम श्रेणी को होती हैं जिनसे कुछ समय के लिए रेडियो सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं। NASA के मुताबिक, सौर ज्वालाओं में सबसे ताकतवर ज्वालाएं X-क्लास की होती हैं। उसके बाद M-क्लास की सौर ज्वालाएं होती हैं जो X-क्लास के मुकाबले 10 गुनी छोटी होती हैं। उसके बाद सी-क्लास, बी-क्लास और ए-क्लास की सौर ज्वालाएं होती हैं जो इतनी कमजोर होती हैं कि धरती पर कोई खास असर नहीं डाल पाती हैं। सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर सूर्य पर हुए विस्फोटों से बनती हैं जो अंतरिक्ष में ऊर्जा, प्रकाश और हाई स्पीड वाले कणों को भेजती हैं।

आदित्य-एल1 का उद्देश्य

सोलर डिस्टर्बेंस की वजह से धरती पर बड़ी तबाही मच सकती है। क्यूबेक ब्लैकआउट उसका एक छोटा सा नमूना था। आदित्य-एल1 इन सोलर डिस्टर्बेंसेज के बारे में जो कुछ भी वैज्ञानिक जानकारी पहले से मौजूद हैं, उसमें कुछ और जोड़ेगा। यह सूरज से जुड़ीं रहस्यमय पहेलियों की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकता है। 'सूर्ययान' 125 दिन में धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु 'एल1' के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। यह वहीं से सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं, गतिविधियों का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट पर धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है।

चंद्रयान से भी कठिन है आदित्य एल 1 का काम, सूर्य से जानकारी जुटाएगा सूर्ययान

आदित्य-एल1 पर लगे 7 उपकरण

आदित्य-एल1 मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में सूर्य के परिमंडल की गर्मी और सौर हवा, सूर्य पर आने वाले भूकंप या 'कोरोनल मास इजेक्शन' (सीएमई), धरती के नजदीक अंतरिक्ष मौसम वगैरह का अध्ययन करना शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन को अंजाम देने के लिए 'आदित्य-एल1' अपने साथ 7 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है। इनमें से 'विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ' (VELC) सूर्य के परिमंडल और सीएमई की गतिशीलता का अध्ययन करेगा।

VELC सूर्ययान का प्राथमिक उपकरण है, जो इच्छित कक्षा तक पहुंचने पर विश्लेषण के लिए हर दिन 1,440 तस्वीरें धरती पर स्थित केंद्र को भेजेगा। यह आदित्य-एल1 पर मौजूद 'सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण' वैज्ञानिक उपकरण है।

'द सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप' यानी SUIT सूर्य के प्रकाशमंडल और वर्णमंडल की तस्वीरें लेगा और सौर विकिरण विविधताओं को मापेगा।

'आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट' (ASWPEX) और 'प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य' (PAPA) नाम के उपकरण सौर पवन और ऊर्जा आयन के साथ-साथ ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे।

'सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर' और 'हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर' (एचईएल1ओएस) विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा क्षेत्र में सूर्य से आने वाली एक्स-रे फ्लेयर का अध्ययन करेंगे।

'मैग्नेटोमीटर' नाम का उपकरण 'एल1' बिंदु पर अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। 'आदित्य-एल1' के उपकरण इसरो के अलग-अलग केंद्रों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं।

ओडिशा और गुवाहाटी हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति, दो न्यायिक अधिकारियों और एक अधिवक्ता को मिली जिम्मेदारी

ओडिशा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए शनिवार को जजों की नियुक्ति की गई। बता दें कि दो न्यायिक अधिकारियों और एक अधिवक्ता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता शिवो शंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चन्द्र बेहेरा के ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जबकि न्यायिक अधिकारी बुडी हाबुंग को गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई दिल्ली। ओडिशा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए शनिवार को जजों की नियुक्ति की गई। बता दें कि दो न्यायिक अधिकारियों और एक अधिवक्ता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति का एलान

कानून मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए अधिवक्ता शिवो शंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चन्द्र बेहेरा के ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की जानकारी साझा की।

इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी बुडी हाबुंग को गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

इनकी हुई नियुक्ति?

अधिवक्ता शिवो शंकर मिश्रा

न्यायिक अधिकारी आनंद चन्द्र बेहेरा

न्यायिक अधिकारी बुडी हाबुंग

बता दें कि अधिवक्ता शिवो शंकर मिश्रा को तकरीबन 30 वर्षों का अनुभव है और उन्हें सिविल, आपराधिक और सेवा कानून में महारत हासिल हैं। इसके अलावा शिवो शंकर मिश्रा की छवि काफी शानदार है।

कानून मंत्री ने क्या कुछ कहा?

अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि केरल हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस सुधा को पदोन्नत किया गया है। बता दें कि अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी किए जाने से पहले दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है। इन न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता के नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। जिनकी नियुक्ति का एलान हो गया है।

'दुनिया के कई देशों में हथियारों से हल होती हैं समस्याएं...', भारत की संस्कृति को लेकर क्या बोले CJI?

सीजेआई ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां समस्याओं को हल करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमारे यहां हिंसा को रोकने लिए संवाद सहिष्णुता की संस्कृति को अपनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के माध्यम से समाज में जो महत्वपूर्ण संदेश जाता है। वह यह है कि हम कानून के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खड़े हैं।

आइजोल। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की आइजोल पीठ की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून का शासन देश और न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों को बनाए रखता है। दरअसल, आइजोल पीठ की नई इमारत के उद्घाटन के अवसर पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संस्थानों ने संवाद, सहिष्णुता और साझा मूल्यों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की संस्कृति विकसित की है, लेकिन कई देश ऐसे हैं, जो सिर्फ शस्त्र और हथियारों के माध्यम से समाधान करते हैं।

सीजेआई ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जहां समस्याओं को हल करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहां हिंसा को रोकने लिए संवाद, सहिष्णुता की संस्कृति को अपनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के माध्यम से समाज में जो महत्वपूर्ण संदेश जाता है। वह यह है कि हम कानून के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खड़े हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन; अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी समेत ये लोग हैं शामिल

एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) के लिए केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाब नबी आजाद भी शामिल हैं। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। एक देश, एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) और गुलाब नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) भी शामिल हैं। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कौन-कौन हैं आठ सदस्यीय समिति में शामिल?

दरअसल, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन केंद्र सरकार 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके अलावा इस समिति में सदस्य के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद को शामिल किया गया है।

इसके साथ ही 'एक देश एक चुनाव' के लिए बनाई गई आठ सदस्य समिति में 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह को भी शामिल किया गया। इसके अलावा लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी इस आठ सदस्य समिति में शामिल हैं।

हाई लेवल बैठकों में हिस्सा लेंगे अर्जुन राम मेघवाल

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक विशेष सदस्य के रूप में समिति की हाई लेवल बैठकों में हिस्सा लेंगे। हालांकि, एक देश-एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दल बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने एक देश-एक चुनाव की आलोचना की है। उन्होंने इसे गलत बताया है।

संसद का विशेष सत्र बुलाया गया

एक दिन पहले केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव को लेकर अभी कमेटी बनाई गई है। इसे लेकर चर्चा की जाएगी और फिर इससे जुड़ी रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। जहां इसे लेकर चर्चा होगी।

BJP ने जम्मू कश्मीर में PDP को समर्थन क्यों दिया था?

विवेक गर्ग एडवोकेट

मोदी सरकार ने सबसे बड़ा जुआ खेला था पीडीपी को समर्थन देकर और बाद में मुफ्ती सरकार गिराने का।

अगर उस विधानसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी एक साथ आकर सरकार बनाने का दावा पेश कर देते तो उनकी सरकार चलती रहती और राज्य में राज्यपाल शासन नहीं लग पाता।

370 हटाने की जो शर्त थी कि राष्ट्रपति से 370 हटाने की अनुशंसा राज्य की विधानसभा को करनी होगी वो शर्त पूरी नहीं होती क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कभी भी यह अनुशंसा नहीं करते। यही वह शर्त थी जिसके भरोसे कश्मीरी लीडर फुदकते थे कि केंद्र में कितनी भी मजबूत सरकार हो 370 हटा नहीं सकती।

उन्हें विश्वास था कि कश्मीर में किसी की भी सरकार बने,

विधानसभा से 370 हटाने की अनुशंसा कभी होगी ही नहीं।

भाजपा का पीडीपी के साथ गठबंधन बहुतो को रास नहीं आया था लेकिन इस गठबंधन का फायदा पूरे देश को हुआ पर बुराई सिर्फ BJP को मिली

इस गठबंधन से भाजपा को सत्ता के अलमारी तथा तिजोरी की चाबी हाथ मे मिली.

अलमारी/तिजोरी खोलकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त किये। वो ऐसें दस्तावेज थे जिसमे केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त पैसे का कांग्रेस आदि पार्टियों द्वारा भारत विरोधी कृत्यों के लिये उपयोग किया जाता था। इतना ही नही पूरे देश से जो टैक्स के मार्फत प्राप्त पैसे का बहुत बडा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर के उपर खर्च किया जाता था उसी पैसे से फारुख/उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आदि ने बहुत सारी जमीन जायदाद संपत्ति जमा की थी जिसके दस्तवेज ढाई साल मे भाजपा ने जमा किये

भ्रष्टाचार के वो दस्तवेज आज केंद्र सरकार के पास है इसलिये फारुख अब्दुला, मेहबुबा मुफ्ती एवं काँग्रेस सरकार चुप बैठी है

भाजपा के साथ जाने की वजह से पीडीपी, अब्दुल्ला और काँग्रेस के लिए अछूत हो गयी।

अब्दुल्ला और कांग्रेस दोनों को लगा कि भाजपा की साथी रही पार्टी को अगर अभी सपोर्ट किया तो उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसी वजह से भाजपा की समर्थन वापसी के बाद दोनों ही दलों ने पीडीपी से किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना को नकार दिया और केंद्र सरकार को J & K में राष्ट्रपति शासन लगाने का मोका मिल गया

यही 370 खत्म होने की नींव पड़ गयी थी क्योंकि विधानसभा की अनुपस्थित में उस राज्य के सम्बंध में राज्यपाल संवैधानिक निर्णय ले सकता है

भाजपा की इस स्ट्रेटेजी को न तो हिंदूद्रोही काँग्रेस, न घमंडी महबूबा और न लालची अब्दुल्ला समझ पाया और उनकी इन्ही मूर्खता का लाभ भारत को मिला।

धारा 370 वैसे तो जम्मू-कश्मीर सरकार की अनुमति के बगैर हट नही सकती पर मोदी SC ST AMENDMENT BILL से कश्मीर में कानून बना चुके थे की अगर कश्मीर में चुनी हुई सरकार न हो तो गवर्नर सारे निर्णय ले सकते है

ये बिल जब पास हो रहा था तब मूर्ख विपक्ष को ये पता ही नही चला कि मोदी ये क्यों कर रहा है!

आरक्षण की बात थी इसलिये विपक्ष ने बड़े जोश से इस बिल का समर्थन किया, पर आरक्षण के बहाने मोदी ने गवर्नर को सारे हक दे दिए और बाद मे गवर्नर ने 370 हटाने की सिफारिश की और जब दोनों सदनों से 370 हटाने का बिल पास हो गया तब राष्ट्रपति ने 370 हटाने के आदेश पर सहमती भी दे दी.

जब 370 धारा हट रही थी तब पता चला कि मोदीजी ये गेम कब से सेट कर रहे थे और धारा 370 हटाने से दो दिन पहले UAPA बिल भी पास किया

मतलब अगर कोई अड़ंगा डालेगा तो सीधा जेल जाएगा।

धारा 370 हटाने की नींव 2014 से रखी गयी थी। पूरे घटनाक्रम में महबूबा मुफ्ती की सबसे बड़ी गलती की उसने मोदी से हाथ मिला कर कश्मीर में अपनी सरकार बनाई। मोदी को बहाना चाहिए था राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो महबूबा की गलतियों की वजह से लगा दिया गया। अगर, महबूबा कोंग्रेस या नेशनल कांफ्रेंस से हाथ मिलाती तो शायद ये संभव न होता।

मोदी के बिछाए शतरंज के इस खेल में सारे प्यादे एक - एक करके गिरते गए, आखिर में बची रानी के लिए वजीर ही काफी था।

"द्वंद कहाँ तक पाला जाए,
युद्ध कहाँ तक टाला जाए,
तू भी है राणा का वंशज,
फेंक जहाँ तक भाला जाए,
दोनों तरफ़ लिखा हो
भारत
सिक्का वही उछाला जाए.!"

आज राहुल गांधी एवं काँग्रेस सरकार पूरे देश को वचन दे रही है कि यदि उन्हे सत्ता मे वापस बिठा जाये तो धारा 370 वापस लाएंगे

क्या आप सभी देशवासीयौ के कर द्वारा प्राप्त हुआ पैसा वापस कश्मीर के ऊपर बर्बाद करके भारत विरोधी कार्यवाही के लिये देना चाहते?

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023